द शूटर

सूरजपुर जिले से प्रकाशित
प्रथम हिन्दी दैनिक

प्रधान संपादक- रूपेश दुबे: 9826169678
संपादक- प्रवीण दुबे: 9165083700

वर्ष-14 अंक-169 | प्रतापपुर, जिला- सूरजपुर छ.ग. से प्रकाशित | गुरूवार 06 अगस्त 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य- 2 रूपये

पहली ही बारिश में बह गई करोड़ों की सड़क, विकास की हकीकत ने खड़े किए कई सवाल

*** तिलसिवां-भैसमर मार्ग पर निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, जांच और कार्रवाई की मांग**

सूरजपुर, 05 अगस्त 2026, द शूटर। सरकारी योजनाओं के जरिए गांवों तक बेहतर सड़क पहुंचाने के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। जिला मुख्यालय सूरजपुर से महज एक किलोमीटर दूर एनएच-43 से तिलसिवां होते हुए भैसमर गोंडपारा तक निमार्णाधीन सड़क पहली ही बारिश में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपये की लागत से बन रही 1.85 किलोमीटर लंबी सड़क का कई हिस्सों में बह जाना अब निर्माण की गुणवत्ता और विभागीय निगरानी पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर रहा है।स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि बारिश ने उसकी परतें उधेड़ दीं। जगह-जगह गिट्टियां उखड़ गईं, सड़क धंस गई और कई स्थानों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। इससे न केवल सरकारी धन के उपयोग पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है।

ग्रामीणों से लगातार शिकायत मिलने के बाद कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू मौके पर पहुंचे और सड़क की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद उन्होंने निर्माण कार्य को लेकर पीएमजीएसवाई विभाग और निर्माण एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए। अविनाश साहू ने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट से चंद दूरी पर यदि करोड़ों रुपये की लागत से बन रही सड़क पहली ही बारिश में बह जाती है, तो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में हो रहे निर्माण कार्यों की स्थिति सहज ही समझी जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह केवल तकनीकी लापरवाही नहीं, बल्कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितता और कथित कमीशनखोरी का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि सड़क का निर्माण रायपुर की जगदंबा कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है, जहां गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। साहू का कहना है कि यदि विभागीय अधिकारी समय-समय पर निर्माण की निगरानी करते, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

कांग्रेस की ओर से पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर को सौंपते हुए सड़क निर्माण की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा सड़क का नए सिरे से गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने की मांग की गई है।अविनाश साहू ने चेतावनी दी कि यदि मामले में केवल औपचारिक जांच कर दोषियों को बचाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।फिलहाल पहली ही बारिश में सड़क के बह जाने से पीएमजीएसवाई के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी फाइलों तक सीमित रह जाता है।

14 दिन बाद भी नहीं जागा प्रशासन: एफसीआई गोदाम की जर्जर दीवारें और खतरा बना नीलगिरी का पेड़, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

*** विश्रामपुर में आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं, भय के साए में गुजर रही लोगों की जिंदगी**

सूरजपुर/विश्रामपुर, 05 अगस्त 2026, द शूटर। विश्रामपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित एफसीआई गोदाम परिसर में करीब 14 दिन पहले बारिश के दौरान दीवार गिरने की घटना के बाद भी हालात नहीं बदले हैं। हादसे में सात परिवारों के मकानों को नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जर्जर दीवारों को हटाने, खतरा बने नीलगिरी के पेड़ों पर कार्रवाई करने और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन दो सप्ताह बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है।स्थानीय नागरिकों का कहना है कि एफसीआई परिसर की कई दीवारें अब भी जर्जर हालत में खड़ी हैं, जबकि बारिश के कारण नीलगिरी के विशाल पेड़ों की जड़ें भी कमजोर हो चुकी हैं। तेज हवा या लगातार बारिश होने पर दीवार या पेड़ गिरने की आशंका बनी हुई है। रेलवे स्टेशन के समीप होने के कारण यहां दिनभर लोगों की आवाजाही रहती है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है।ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर खतरे से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक न तो दीवारों को हटाया गया और न ही पेड़ों को सुरक्षित करने की दिशा में कोई पहल हुई है। वहीं, जिन परिवारों के मकानों को नुकसान पहुंचा था, उन्हें अब तक उचित मुआवजा भी नहीं मिल सका है।क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से तत्काल जर्जर दीवारों को हटाने, नीलगिरी के पेड़ों का तकनीकी परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत और मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।

रामलला के जयघोष के बीच श्रद्धालुओं का जत्था रवाना, जनपद अध्यक्ष स्वाति सिंह और सीईओ ने दी शुभकामनाएं

सूरजपुर, 05 अगस्त 2026 द शूटर। आस्था, विश्वास और श्रद्धा से भरे माहौल में जनपद पंचायत सूरजपुर से रामलला तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के दल को विधिवत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के चेहरों पर भगवान श्रीराम के दर्शन की उत्सुकता साफ झलक रही थी। परिजनों ने शुभकामनाओं के साथ यात्रियों को विदा किया तो वातावरण ₹जय श्रीराम₹ के उद्घोष से गूंज उठा।जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वाति सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने सभी यात्रियों की सुखद, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मिक शांति और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है।उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आग्रह भी किया।

कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शासन द्वारा संचालित रामलला तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से ऐसे अनेक श्रद्धालुओं का वर्षों पुराना सपना साकार हो रहा है, जो आर्थिक या अन्य कारणों से अयोध्या धाम के दर्शन नहीं कर पाते थे। यह पहल उन्हें अपनी आस्था के केंद्र तक पहुंचने का अवसर प्रदान कर रही है।इस अवसर पर जनपद पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के परिजन उपस्थित रहे। सभी ने यात्रियों को शुभकामनाओं के साथ विदा किया और उनकी सकुशल वापसी की कामना की।

38 गांवों की बुझी उम्मीदों को रोशन करने सड़क पर उतरेगी आप, 7 अगस्त को बिहारपुर में धरना और रैली

सूरजपुर, 05 अगस्त 2026 द शूटर। ओड़गी विकासखंड के दूरस्थ चांदनीझबिहारपुर अंचल के 38 गांवों में वर्षों से स्थायी बिजली व्यवस्था का इंतजार कर रहे ग्रामीणों की आवाज अब एक बार फिर आंदोलन का रूप लेने जा रही है। अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर हजारों लोगों की पीड़ा को मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी ने 7 अगस्त (शुक्रवार) को बिहारपुर थाना परिसर के समीप एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन की घोषणा की है। प्रदर्शन दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जिसके बाद बिहारपुर बाजार में रैली भी निकाली जाएगी।पार्टी का कहना है कि लगभग दस वर्ष पहले जिन गांवों में सोलर व्यवस्था स्थापित की गई थी, वह अधिकांश स्थानों पर पूरी तरह ठप हो चुकी है। विद्युत विस्तार योजना को स्वीकृति मिलने के बावजूद आज तक काम पूरा नहीं हो सका। नतीजतन 38 गांवों के हजारों परिवार आज भी अंधेरे में जीवन बिताने को विवश हैं। बिजली के अभाव का असर बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल व्यवस्था, सिंचाई, संचार और रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है।आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव लव कुमार ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर 4 नवंबर 2025 को जिला कलेक्टर को विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने लगातार 10 दिनों तक शांतिपूर्ण धरना देकर अपनी मांग रखी थी। उस समय प्रशासन ने एक माह के भीतर विद्युत आपूर्ति शुरू कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब आश्वासन धरातल पर नहीं उतरता, तब जनता को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है।जिलाध्यक्ष रवि जायसवाल ने बताया कि धरना-प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद बिहारपुर बाजार में रैली निकालकर क्षेत्र की बिजली समस्या की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को पूरा सहयोग दिया जाएगा।धरना-प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दुबे, सरगुजा जोन सह प्रभारी नूर हसन, सरगुजा लोकसभा अध्यक्ष इंद्रदेव नाग, लोकसभा सचिव लव कुमार सहित पार्टी के जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीणों के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र की जनता, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से इस जनहित के आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि यह किसी राजनीतिक लाभ का नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन में उजाला लाने का संघर्ष है, जो वर्षों से बिजली जैसी मूलभूत सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों की उम्मीद अब इस बात पर टिकी है कि इस बार उनकी आवाज केवल धरना स्थल तक सीमित न रह जाए, बल्कि जिम्मेदार तंत्र तक पहुंचकर ठोस कार्रवाई का रास्ता भी तैयार करे।

बायपास की बदहाल सड़क पर फूटा जनाक्रोश, कांग्रेस का चक्का जाम, प्रशासन ने एक सप्ताह में मरम्मत का दिया भरोसा

सूरजपुर, 05 अगस्त, द शूटर। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की पहचान मानी जाती हैं, लेकिन जब वही सड़कें लोगों के लिए रोजाना खतरे का कारण बनने लगें तो आक्रोश स्वाभाविक है। सूरजपुर के बायपास और केतका रोड की लंबे समय से चली आ रही जर्जर स्थिति को लेकर बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सूरजपुर (ग्रामीण) ने बड़ा आंदोलन करते हुए अंबेडकर चौक में चक्का जाम किया। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज कार्यकताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी यातायात रोक दिया, जिससे कुछ समय तक आवागमन प्रभावित रहा।ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जफर हैदर के नेतृत्व में आयोजित बैठक में क्षेत्र की जनसमस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में खराब सड़क, स्मार्ट मीटर के कारण बढ़ते बिजली बिल, 400 यूनिट बिजली योजना को पुनः लागू करने सहित कई जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम जनता लगातार मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग बायपास एवं केतका रोड की दुर्दशा के विरोध में अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां लंबे समय तक चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बायपास और केतका रोड क्षेत्र के प्रमुख मार्ग हैं, लेकिन सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। जगह-जगह गड्ढों के कारण वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, मरीजों और आम राहगीरों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। बरसात के दिनों में हालात और भी गंभीर हो जाते हैं तथा दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है।

प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज कार्यकताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलने पर तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यपालन अभियंता मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से चर्चा कर बायपास एवं केतका रोड की मरम्मत का कार्य एक सप्ताह के भीतर प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया।कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उनका कहना था कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा का मुद्दा है।इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भगवती राजवाड़े, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज डालमिया, नगर पालिका अध्यक्ष कुसुमलता राजवाड़े, इस्माईल खान, संजय डोसी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीप्ति स्वाई, आनंद कुंवर, आशीष यादव, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आकाश साहू, भावना सिंह नेताम, वीरेंद्र मिश्रा, नरसिंह नारायण, दिलीप सोनी, हुपेश प्रजापति, निर्मल साहू, राजकुमार सिंह, हरकलाल राजवाड़े, इंद्रजीत शर्मा, रश्मि शर्मा, वीणा शर्मा, गीता पुरी, राजेश साहू, शाहरुख खान, ललन पांडे, प्रवीण सोनी, रितेश जायसवाल, शिवम साहू, यश साहू, शिवांश इमालिया, नीरज सिंह, अमित पैकरा, नितेश साहू, रोहन सिंह, जयसाय सिंह, विनय सिंह, नेम कुमार, अब्बास अख्तर, खेलसाय सिंह, तुलेश्वर सिंह, अजय रवि, राजलाल राजवाड़े, नन्हू रवि, अविनाश साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

संस्कारवर्धन फाउंडेशन स्कूल
Reg.No. 122202244473
Sanskarvardhan Foundation Society अन्तर्गत संचालित
Recognized by the Government of Chhattisgarh
Recognition No. 15528
ADMISSION
CALL NOW 8817059456
OPEN
Admission Open
Class 1
Classes- Play To Class-2
nursery
PLAY SCHOOL
LKG
UKG
शनि मंदिर के पास, पॉवर हाउस रोड नमना कला
अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)
Email- sanskarvardhanfoundation@gmail.com
Website- www.sanskarvardhanfoundation.com
Contact No. 8817059456

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 140 संविदा पदों के लिए 4109 आवेदन, 2604 पात्र और 1463 अपात्र

कोरिया-एमसीबी जिले के आवेदकों की पात्र-अपात्र सूची जारी, 17 अगस्त तक दावा-आपत्ति का मौका

*** पात्र-अपात्र की सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट में की गई है प्रसारित**

बैकुण्ठपुर। द शूटर।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कोरिया एवं एमसीबी जिले में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों की पात्र एवं अपात्र सूची जारी कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया द्वारा 12 जून 2026 को कुल 140 रिक्त संविदा पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कोरिया जिले के 27 तथा एमसीबी जिले के 113 पद शामिल थे।
निर्धारित प्रारूप में आवेदकों से आवेदन 3 जुलाई 2026 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया में पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद कोरिया एवं एमसीबी जिले के विभिन्न पदों के लिए पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

4067 आवेदन पात्र-अपात्र सूची में शामिल

प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के अनुसार कोरिया जिले में 974 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 530 पात्र तथा 444 अपात्र पाए गए। वहीं एमसीबी जिले में 3093 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 2074 पात्र और 1019 अपात्र पाए गए। दोनों जिलों को मिलाकर कुल 4067 आवेदन पात्र-अपात्र सूची में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 42 आवेदन

रिजेक्ट किए गए हैं। इस प्रकार कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 4109 है।

फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर और सीएचओ पदों पर अधिक आवेदन

जारी सूची के अनुसार विभिन्न पदों के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फार्मासिस्ट पद के लिए दोनों जिलों में कुल 227 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 167 पात्र और 60 अपात्र हैं। नर्सिंग ऑफिसर (पीएचसी) के लिए कुल 158 आवेदन में 102 पात्र तथा 56 अपात्र पाए गए। इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद के लिए कुल 531 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 300 पात्र और 231 अपात्र हैं। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए 438 आवेदन में 312 पात्र और 126 अपात्र पाए गए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 321 आवेदन में 229 पात्र और 92 अपात्र हैं।

17 अगस्त शाम 5 बजे तक दावा-आपत्ति

कोरिया एवं एमसीबी जिले के रिक्त संविदा पदों के लिए जारी पात्र एवं अपात्र सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है। इसके अलावा सूची जिला प्रशासन की वेबसाइट https://korea.gov.in/en/notice_category/recruitment पर भी प्रकाशित की गई है।
जिन आवेदकों को पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करनी है, वे 17 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे तक अपना दावा-आपत्ति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश सहित ऐतिहासिक घोषणाओं का सर्व रविदास समाज ने किया स्वागत

बैकुण्ठपुर। द शूटर। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई ऐतिहासिक घोषणाओं का सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ ने जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें समाज के सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक लाल कुर्रे ने मुख्यमंत्री के प्रति समाज की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्णयों से गुरु रविदास महाराज के आदर्शों को नई ऊर्जा मिलेगी और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। अशोक लाल कुर्रे ने बताया कि 4 अगस्त 2026 को रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित संत रविदास जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें माघ पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना प्रमुख है। इसके साथ ही गुरु रविदास के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रारंभ करने तथा प्रत्येक वर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यह सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा भी की गई।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में संत रविदास के संदेश को अंकित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। वहीं नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नाम संत गुरु रविदास के नाम पर रखने की घोषणा को भी समाज ने ऐतिहासिक निर्णय बताया। इसके अतिरिक्त संत रविदास जयंती के अवसर पर राज्य में मांस एवं मदिरा की दुकानों को बंद रखने की घोषणा को भी समाज ने सकारात्मक पहल बताया। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक लाल कुर्रे ने कहा कि मुख्यमंत्री के इन निर्णयों से संत गुरु रविदास के प्रसिद्ध संदेश *मन चंगा तो कठौती में गंगा* को व्यापक स्तर पर सम्मान मिलेगा तथा समाज में समानता, शिक्षा, सद्भाव और भाईचारे की भावना को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये घोषणाएं केवल रविदास समाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात करेंगी। सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय समाज के सम्मान, एकता और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान प्रदान करेगा। समाज का विश्वास है कि इन ऐतिहासिक घोषणाओं से संत रविदास के विचार अधिक व्यापक रूप से जन-जन तक पहुंचेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।

हर जरूरतमंद को समय पर मिले अपना आशियाना, पीएम आवास के लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

रामानुजनगर, 05 अगस्त 2026 द शूटर। सिर पर पक्की छत का सपना हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। इसी उम्मीद को जल्द हकीकत में बदलने के उद्देश्य से जनपद पंचायत रामानुजनगर में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने लंबित आवास निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
समीक्षा के दौरान सभी पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों को निर्देशित किया गया कि जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य अभी अधूरे हैं, उन्हें तेजी से पूरा कराया जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल किया जाए। सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि

हजारों जरूरतमंद परिवारों के सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का आधार है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि योजना से संबंधित सभी जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट समय पर पोर्टल में दर्ज की जाए, ताकि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो सके और किसी भी स्तर पर विलंब की स्थिति उत्पन्न न हो।
बैठक में सीईओ ने दो टूक कहा कि कार्यों में लापरवाही, उदासीनता या लक्ष्य प्राप्ति में अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को अपने-अपने ग्राम पंचायतों का नियमित भ्रमण कर निमार्णाधीन आवासों की सतत निगरानी करने तथा शत-प्रतिशत लक्ष्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि कोई भी पात्र परिवार अपने पक्के घर के अधिकार से वंचित न रहे और प्रत्येक हितग्राही का आवास निर्माण गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराया जाए, ताकि शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

सेंट जोसेफ स्कूल बैकुंठपुर के छात्र सूर्यांश पाण्डेय ने रचा इतिहास, अखिल भारतीय हिंदी ओलंपियाड में हासिल की इंटरनेशनल रैंक-1

बैकुण्ठपुर। द शूटर। शिक्षा, प्रतिभा और निरंतर मेहनत का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सेंट जोसेफ स्कूल, बैकुंठपुर के कक्षा 10वीं के मेधावी छात्र सूर्यांश पाण्डेय ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिस पर न केवल उनके विद्यालय और परिवार बल्कि पूरे बैकुंठपुर एवं कोरिया जिले को गर्व है। शकुंतला कॉलोनी निवासी सूर्यांश पाण्डेय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज कराई हैं। सबसे बड़ी सफलता उन्हें सिल्वरजोन ओलंपियाड फाउंडेशन (SilverZone Olympiad Foundation) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अखिल भारतीय हिंदी ओलंपियाड में मिली। इस प्रतियोगिता में सूर्यांश ने 100 में से 100 अंक प्राप्त कर इंटरनेशनल रैंक-1 हासिल की। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भारत सहित कई देशों के हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया था। ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर प्रथम स्थान प्राप्त करना उनकी असाधारण प्रतिभा, विषय पर मजबूत पकड़ और कठिन परिश्रम का प्रमाण है। सूर्यांश ने केवल ओलंपियाड में ही नहीं, बल्कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में भी अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया। हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम में उन्होंने 98.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। उनकी इस सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। सूर्यांश की प्रतिभा केवल हिंदी विषय

तक सीमित नहीं है। वे एक ऑलराउंडर छात्र हैं, जिन्होंने विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन जैसे विभिन्न विषयों की ओलंपियाड प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन किया। इस शैक्षणिक सत्र में उन्होंने विभिन्न विषयों में कुल 8 पदक जीतकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। शिक्षा के साथ-साथ सूर्यांश संगीत के क्षेत्र में भी समान रूप से प्रतिभाशाली हैं। सुर और ताल पर उनकी पकड़ उन्हें एक संवेदनशील और रचनात्मक विद्यार्थी के रूप में पहचान दिलाती है। वे पढ़ाई के साथ-साथ संगीत एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों को भी पूरा समय और महत्व देते हैं। यही संतुलन उनकी सफलता का महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। सूर्यांश की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर सेंट जोसेफ स्कूल के प्राचार्य, शिक्षकों एवं समस्त स्टाफ ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि सूर्यांश की सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और सीखने की निरंतर इच्छा का परिणाम है। उनका प्रदर्शन विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है।
अपनी सफलता पर सूर्यांश पाण्डेय ने इसका श्रेय अपनी माता प्रियंका पाण्डेय, पिता अमरेश पाण्डेय, विद्यालय के शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन तथा अपने नियमित अभ्यास और दृढ़ संकल्प को दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। सूर्यांश पाण्डेय की यह उपलब्धि बैकुंठपुर और कोरिया जिले के लिए गर्व का विषय है। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि छोटे शहरों के विद्यार्थी भी अपनी प्रतिभा, समर्पण और कठिन परिश्रम के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं।

सीएम हेल्पलाइन शिकायत की पत्र प्रति नहीं मिलने पर आयुक्त से जांच की मांग

*** शिकायतकर्ता का आरोप- एसडीएम कार्यालय ने कहा प्रतिलिपि नहीं दी जाती, जबकि आयुक्त कार्यालय ने बताया कि शिकायतकर्ता को प्रति मिलनी चाहिए थी**

बैकुण्ठपुर, 05 अगस्त। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज एक शिकायत के संबंध में आयुक्त कार्यालय, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर द्वारा जारी पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता महेन्द्र ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए आयुक्त कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत की है।
शिकायतकर्ता महेन्द्र के अनुसार, उन्होंने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170(ख) से संबंधित विषय पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के संबंध में आयुक्त कार्यालय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर द्वारा पत्र क्रमांक 4623, दिनांक 20 जुलाई 2026 जारी किया गया था।
महेन्द्र का ने बताया है कि जब उन्होंने उक्त पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, बैकुण्ठपुर के वाचक मानसाय एक्का से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि शिकायतकर्ता को प्रतिलिपि नहीं दी जाती तथा कलेक्टर कार्यालय को भी इसकी प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती। इसके बाद शिकायतकर्ता ने आयुक्त कार्यालय अम्बिकापुर के दूरभाष क्रमांक +91 77742 41501 पर संपर्क किया। उनका कहना है कि वहां से उन्हें जानकारी दी गई कि पत्र क्रमांक 4623 दिनांक 20 जुलाई 2026 की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। दोनो कार्यालयों से मिली अलग-अलग जानकारी के बाद मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता ने आयुक्त से पूरे मामले की जांच कर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि पत्र की प्रति उन्हें क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा गलत अथवा भ्रामक जानकारी दी गई है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने और संबंधित पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधिकारी की अनूठी पहल, न्योता भोज के साथ अनुशासन, शिक्षा और जीवन लक्ष्य पर दिया प्रेरक संदेश

सूरजपुर /द शूटर।शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर अंतर्गत माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक, नैतिक एवं व्यक्तित्व विकास को समर्पित प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की सहभागिता ने विद्यार्थियों में उत्साह, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोंडागांव कपिल चंद्रा के सौजन्य से विद्यालय में स्नेह एवं आत्मीयता से परिपूर्ण न्योता भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को खीर, पूड़ी, मिठाई सहित स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण और कैरियर मार्गदर्शन के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश देवांगन को विद्यालय में आमंत्रित किया गया। अधिकारी ने बच्चों के साथ बैठकर संवाद किया और उन्हें शिक्षा, संस्कार तथा अनुशासित जीवन का महत्व समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व, लक्ष्य निर्धारण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सुरक्षित भविष्य, आत्मविश्वास और अनुशासन जैसे विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश दिया। विद्यालय परिवार ने दोनों पुलिस अधिकारियों की इस अनुकरणीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, सामाजिक जागरूकता, अनुशासन और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों ने भी इन कार्यक्रमों को प्रेरणादायी बताते हुए भविष्य में ऐसे आयोजनों की अपेक्षा व्यक्त की। कार्यक्रम के समापन पर सुनील दत्त तिवारी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन का छात्र हित में अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य सुनील कुजूर, ओमप्रकाश राजवाड़े, कुमारी समृद्धि चंद्राकर सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

सशक्त बचपन, समृद्ध छत्तीसगढ़:बच्चों के पोषण, संरक्षण और सर्वांगीण विकास का नया अध्याय

*** पोषण पखवाड़ा में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर**

डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर
(उप, संचालक)

रायपुर, 05 अगस्त 2026 द शूटर । किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति उसके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से मापी जाती है। छत्तीसगढ़ ने इसी सोच को आधार बनाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी नीतियों और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के सक्रिय नेतृत्व में प्रदेश में बच्चों के पोषण, संरक्षण और भविष्य निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आईसीडीएस, मिशन वात्सल्य, पोषण अभियान और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन ने राज्य को बाल विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है।

आंगनबाड़ी केंद्र बन रहे बाल विकास के आधुनिक केंद्र

प्रदेश में 11 हजार 490 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और आकर्षक बनाने का कार्य तेजी से जारी है। इन केंद्रों में बिल्डिंग एज लर्निंग एड (इंछअ) पेंटिंग, पोषण वाटिका, खेल एवं शिक्षण आधारित गतिविधियों जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे बच्चे सीखने के साथ आनंदमय वातावरण में विकसित हो सकें।मनरेगा अभिसरण के माध्यम से 2 हजार 337 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। वहीं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 191 नए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। नियद नेल्ला नार 2.0 के तहत 10 जिलों में 12 हजार 964 आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं।मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकताओं की संख्या 51 हजार 45 से बढ़कर 52 हजार 258 तथा सहायिकाओं की संख्या 44 हजार 826 से बढ़कर 51 हजार 548 हो गई है, जिससे सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार आया है।

कुपोषण पर प्रभावी प्रहार

छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों में कुपोषण कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के अनुसार 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग में 7.82 प्रतिशत की कमी, वेट में 4.36 प्रतिशत की कमी, अंडरवेट में 2.76 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दिसंबर 2023 में जहां बौनापन की दर 30.27 प्रतिशत थी, वह जून 2026 तक घटकर 22.45 प्रतिशत रह गई। यह उपलब्धि पोषण प्रबंधन, नियमित मॉनिटरिंग, सामुदायिक सहभागिता और आंगनबाड़ी आधारित सेवाओं के प्रभावी संचालन का परिणाम है।

पोषण अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन

राष्ट्रीय पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान छत्तीसगढ़ ने देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य प्रति आंगनबाड़ी गतिविधियों में प्रथम स्थान पर रहा। अप्रैल 2025 के पोषण पखवाड़ा में भी छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया।प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर 2025 के पोषण माह के दौरान 71 हजार 887 गतिविधियां और अप्रैल 2026 के पोषण पखवाड़ा में 34 लाख 93 हजार 474 गतिविधियां आयोजित की गईं। साथ ही स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए रेडी टू ईट इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल शुरू हो चुकी है।

मिशन वात्सल्य से बच्चों को सुरक्षा और संबल

अनाथ, परित्यक्त और विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन वात्सल्य प्रभावी सुरक्षा कवच बनकर उभरा है। राज्य में बाल देखरेख संस्थाओं की संख्या बढ़कर 109 हो गई है।

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के माध्यम से सैकड़ों बच्चों को शिक्षा, देखभाल और पुनर्वास का लाभ मिला है। चाइल्ड हेल्पलाइन में प्राप्त 1 लाख 65 हजार 979 कॉलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हजारों मामलों का निराकरण किया गया।बाल संरक्षण सेवाओं के विस्तार का प्रभाव दत्तक ग्रहण और स्पॉन्सरशिप योजनाओं में भी स्पष्ट दिखाई देता है। दत्तक ग्रहण से लाभान्वित बच्चे 42 से बढ़कर 234 और स्पॉन्सरशिप से लाभान्वित बच्चे 767 से बढ़कर 2 हजार 37 हो गए हैं। यह वृद्धि बच्चों को पारिवारिक वातावरण और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान ने सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक सक्रियता दोनों को नई दिशा दी है। बाल विवाह प्रतिरोध अधिकारियों की संख्या बढ़कर 1 हजार 382 हो गई है। इसके परिणामस्वरूप रोके गए बाल

विवाहों की संख्या 109 से बढ़कर 888 तक पहुंच गई है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बेटियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव का संकेत है।

भविष्य की मजबूत नींव

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में संचालित ये प्रयास छत्तीसगढ़ के लाखों बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षा, शिक्षित और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं।आधुनिक आंगनबाड़ी व्यवस्था, पोषण सुधार, बाल संरक्षण सेवाओं का विस्तार और बाल विवाह उन्मूलन जैसे बहुआयामी प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को बाल विकास के क्षेत्र में एक प्रेरणादायी और आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया है।

सशक्त बचपन ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव है और राज्य सरकार उसी नींव को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।

प्रतिबंधित डेयरी उत्पादों पर सघन जांच का दावा, लेकिन जनजागरूकता और विभागीय संवाद अब भी अधूरा

सूरजपुर, 05 अगस्त 2026, द शूटर। जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर समय-समय पर अभियान चलाए जाने के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जनस्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर विभाग और आम नागरिकों के बीच प्रभावी संवाद आज भी नदारद है। अक्सर निरीक्षण के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सक्रियता प्रदर्शित कर दी जाती है, जबकि उपभोक्ताओं को जागरूक करने, मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान बताने और शिकायतों पर पारदर्शी कार्रवाई की जानकारी साझा करने जैसी पहलें अपेक्षित स्तर पर दिखाई नहीं देतीं। ऐसे माहौल में राज्य शासन के निर्देश पर प्रतिबंधित एनालॉग डेयरी उत्पादों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सूरजपुर और बिश्रामपुर क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया।

अभिहित अधिकारी पुष्पराज चौहान के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम प्रकाश जायसवाल एवं नमूना सहायक दीपा साहू के साथ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और डेयरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कहीं प्रतिबंधित एनालॉग पनीर या अन्य एनालॉग डेयरी उत्पादों का निर्माण, भंडारण अथवा उपयोग तो नहीं किया जा रहा है।सूरजपुर क्षेत्र में कृष्णा डेयरी, जय डेयरी, बाबा होटल, गुड्डू स्वीट्स, गोलू स्वीट्स, पंडित स्वीट्स, गोपाल डेयरी और कान्हा डेयरी की जांच की गई। वहीं बिश्रामपुर में सालु स्वीट्स, जय डेयरी, संदीप स्वीट्स, दूध डेयरी, सुहानी डेयरी, सोनी होटल, जलतरंग स्वीट्स, वीरेंद्र सब्जी भंडार, कृशु डेयरी और श्याम डेयरी का निरीक्षण किया गया।खाद्य सुरक्षा टीम के अनुसार जांच के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित एनालॉग डेयरी उत्पाद या उससे संबंधित संदिग्ध कच्चा माल नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान व्यवसायियों को शासन की अधिसूचना की जानकारी देते हुए ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण और विक्रय से पूरी तरह दूर रहने के निर्देश भी दिए गए।विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि किसी भी प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस प्रकार के जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रखने की बात कही गई है।हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवल औचक निरीक्षण और प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर देने से मिलावटखोरी जैसी गंभीर समस्या पर स्थायी नियंत्रण संभव नहीं है। उनका मानना है कि विभाग को नियमित जनजागरूकता अभियान चलाने, उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने, खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर हुई कार्रवाई को पारदर्शी ढंग से सामने लाने की दिशा में भी गंभीर पहल करनी चाहिए। जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में भरोसा तभी मजबूत होगा, जब निरीक्षण के साथ-साथ जवाबदेही और संवाद भी समान रूप से दिखाई देगा।

97 गांवों में रोशनी की नई उम्मीद, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से 11.62 करोड़ की विद्युत विस्तार योजना को मिली मंजूरी

रायपुर/सूरजपुर, 05 अगस्त 2026, द शूटर। बरसों से अंधेरे में जीवन गुजार रहे दूरस्थ और जनजातीय इलाकों के लिए अब उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। जिन बस्तियों में ढलते सूरज के साथ ही दिनचर्या थम जाती थी, वहां अब बिजली की रोशनी पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधानसभा की विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के लगातार प्रयासों से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के तहत भटगांव विधानसभा क्षेत्र के 97 गांवों में विद्युत विस्तार कार्य को स्वीकृति मिल गई है।करीब 11 करोड़ 62 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित इस योजना के माध्यम से सूरजपुर जिले के दूरस्थ गांवों और टोलों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। लंबे समय से मूलभूत सुविधा से वंचित हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए यह योजना केवल बिजली का विस्तार नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली पहल मानी जा रही है।शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखंड भैयाथान के 36 गांवों के लगभग 109 मोहल्लों एवं पारों, ओड़गी विकासखंड के 32 गांवों के 68 मोहल्लों तथा सूरजपुर विकासखंड के 29 गांवों के 53 मोहल्लों में

विद्युत विस्तार का कार्य किया जाएगा। इससे अनेक ऐसे गांव भी लाभान्वित होंगे, जहां आज तक बिजली की सुविधा सीमित या पूरी तरह अनुपलब्ध रही है।

ग्रामीणों का मानना है कि बिजली पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी, महिलाओं को घरेलू कार्यों में सुविधा मिलेगी, पेयजल व्यवस्था मजबूत होगी और कृषि व छोटे स्वरोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। जनजातीय अंचलों में विकास की गति तेज होने के साथ जीवन स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा विकास की रोशनी को अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचाने की है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्वीकृति भटगांव विधानसभा के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि हर घर तक बिजली पहुंचने से ग्रामीण अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।जनजातीय अंचलों के लिए यह योजना केवल विद्युत विस्तार का कार्य नहीं है, बल्कि उन परिवारों के सपनों को उजाला देने की पहल है, जिन्होंने वर्षों तक अंधेरे में बेहतर भविष्य का इंतजार किया। अब उम्मीद है कि रोशनी के साथ इन गांवों में विकास की नई सुबह भी दस्तक देगी।

स्वागत से शुरू होती शिक्षा, खेल-गीतों से संवर रहा नौनिहालों का भविष्य: आंगनबाड़ी केंद्र बने बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहली पाठशाला

रायपुर,05 अगस्त 2026 द शूटर। बच्चों के जीवन के शुरूआती वर्ष उनके भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसी सोच को केंद्र में रखकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल पोषण वितरण केंद्र नहीं, बल्कि प्रारंभिक शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य और बाल विकास के समग्र केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में नवाचार आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए आनंदमय और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

बलरामपुर जिले के स्कूल पारा भनौरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र ने इस दिशा में एक प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह केंद्र आज नन्हे बच्चों के लिए सीखने, खेलने, संवाद करने और आत्मविश्वास विकसित करने की पहली पाठशाला बनकर उभरा है।

स्वागत चार्ट से बढ़ रहा आत्मविश्वास

केंद्र की सबसे विशेष पहल स्वागत चार्ट है। केंद्र में आने वाला प्रत्येक बच्चा अपनी पसंद के अनुसार चार्ट पर बने चित्रों में से किसी एक का चयन करता है। इसमें गले मिलना, ताली देना, हाथ मिलाना, मुट्ठी मिलाना, कोहनी मिलाना और नमस्ते जैसे विकल्प शामिल हैं। बच्चा जिस तरीके का चयन करता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसी प्रकार उसका आत्मीय स्वागत करती हैं।इस छोटी लेकिन प्रभावशाली पहल से बच्चों का संकोच कम हो रहा है, वे स्वयं को सम्मानित और स्वीकार्य महसूस कर रहे हैं तथा केंद्र में प्रवेश करते ही मुस्कुराते हुए गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। इससे सामाजिक व्यवहार, संवाद कौशल, भावनात्मक अभिव्यक्ति और सकारात्मक सोच का भी विकास हो रहा है।

गीत, खेल और गतिविधियों से सीख रहे बच्चे

केंद्र में प्रतिदिन प्रार्थना, स्वागत गीत, समूह गतिविधियां, शैक्षणिक खेल, कहानी-कथन, चित्र पहचान, रंग पहचान, अक्षर और अंक ज्ञान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। बच्चों को पारंपरिक रटने की बजाय खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षण पद्धति से सीखने का अवसर दिया जा रहा है।

गीत, कविता, लय और रचनात्मक खेलों के माध्यम से बच्चे सहजता से नई बातें सीख रहे हैं। इससे उनका मानसिक, भाषाई, सामाजिक और बौद्धिक विकास तेजी से हो रहा है। साथ ही उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, समूह में कार्य करने की आदत और आत्मविश्वास भी विकसित हो रहा है, जो उन्हें विद्यालय में प्रवेश के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर रहा है।

पौष्टिक आहार से मजबूत हो रहा स्वास्थ्य

राज्य शासन द्वारा बच्चों के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र में निर्धारित मेन्यू के अनुसार

पौष्टिक नाश्ता और गर्म पका हुआ मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इससे बच्चों को आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व मिल रहे हैं, जो उनके शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसके साथ ही बच्चों की उपस्थिति, वजन, ऊंचाई, स्वास्थ्य स्थिति और विकास की नियमित निगरानी की जाती है। गर्भवती और धात्री माताओं को भी संतुलित आहार, स्वच्छता, स्तनपान, टीकाकरण और शिशु देखभाल संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।

स्नेहपूर्ण वातावरण बना बच्चों का दूसरा घर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बच्चों के<लिए परिवार जैसा स्नेहपूर्ण, सुरक्षित और बाल-अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। यही कारण है कि बच्चे बिना किसी झिझक के केंद्र में समय बिताते हैं और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं।

आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बालिका सौम्या की माता श्रीमती सोनम सोनी बताती हैं कि यह केंद्र बच्चों के लिए केवल पाठशाला नहीं, बल्कि दूसरा घर बन गया है। स्वागत चार्ट, खेल-आधारित शिक्षण और आत्मीय व्यवहार ने बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह बढ़ाया है। अब बच्चे स्वयं खुशी-खुशी आंगनबाड़ी जाने के लिए तैयार होते हैं और घर लौटकर गीत, कविताएं तथा दिनभर सीखी नई बातें उत्साहपूर्वक साझा करते हैं।

बाल विकास का सशक्त मॉडल बन रहे आंगनबाड़ी केंद्र

प्रदेश में संचालित ऐसी नवाचारी गतिविधियां यह दशार्ती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों की भूमिका अब केवल पोषण तक सीमित नहीं रही। वे प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संस्कार और सामाजिक विकास के समेकित केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं।

स्कूल पारा भनौरा का आंगनबाड़ी केंद्र इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जहां शिक्षा का आरंभ मुस्कान और स्वागत से होता है, वहां बच्चों का भविष्य भी आत्मविश्वास, सीखने की खुशी और बेहतर अवसरों से भर जाता है। यह केंद्र वास्तव में बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव तैयार करने वाली पहली पाठशाला बन चुका है।

सेवा सेतु बना आमजन का सहारा, एक दिन में मिला निवास प्रमाणपत्र, बच्चों के भविष्य की चिंता हुई दूर

सूरजपुर, 05 अगस्त 2026 द शूटर। कभी एक छोटे से प्रमाणपत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब बदलती व्यवस्था लोगों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान ला रही है। छत्तीसगढ़ शासन की सेवा सेतु योजना आम नागरिकों के लिए भरोसे का माध्यम बनती जा रही है।सूरजपुर तहसील के महंगाव निवासी यश कुमार ने अपनी पुत्री सुरभी और पुत्र गौरव कुमार के निवास प्रमाणपत्र के लिए सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन किया। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद दोनों बच्चों के निवास प्रमाणपत्र मात्र एक ही दिन में जारी कर दिए गए।यश कुमार ने बताया कि समय पर प्रमाणपत्र मिलने से बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकीं। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु ने सरकारी सेवाओं को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाकर आम लोगों का विश्वास मजबूत किया है। उन्होंने इस पहल के लिए शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

मानसून का बढ़ता खतरा, रबी फसल पर संकट

मानसून का बढ़ता खतरा 2026-27 में भारतीय खेती को मौसम से जुड़े गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। अल नीनो का असर दिख रहा है। हम चार महीने के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून चक्र (जून से सितंबर) के आधे रास्ते पर हैं, और स्थिति चिंताजनक है। इससे पहले, जून में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के देर से आने और धीमी गति के बावजूद, जुलाई में हुई भारी बारिश ने सूखे जैसे हालात को रोक दिया और खेती से जुड़े लोगों को राहत दी। फिर भी, 31 जुलाई तक देश भर में बारिश की कमी 13 प्रतिशत (-13%) रही है। 36 मौसम संबंधी उप-क्षेत्रों में से 17 में अभी भी बारिश की भारी कमी है। इनमें पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, अब तक बारिश का भौगोलिक वितरण संतोषजनक नहीं रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (क्टऊ) ने हाल ही में कहा है कि अगस्त और सितंबर में बारिश सामान्य से कम होगी। इससे खरीफ फसल की स्थिति और पैदावार की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ना तय है। खरीफ की संभावना कमजोर 24 जुलाई तक, धान, दालें, मोटे अनाज, तिलहन और कपास जैसी मुख्य फसलों के तहत बोया गया रकबा पिछले साल इसी समय के स्तर से पीछे चल रहा है। सामान्य रकबे (पांच साल का औसत) तक पहुंचने में अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन बुवाई का समय असल में जुलाई के मध्य तक खत्म हो चुका था। इसलिए, रकबे के बारे में आगे की रिपोर्ट में केवल थोड़ी बढ़ोतरी ही दिखेगी, क्योंकि राज्यों द्वारा बोए गए रकबे की रिपोर्टिंग में आमतौर पर देरी होती है। दूसरे शब्दों में, यह बात तेजी से साफ हो रही है कि 2026-27 में खरीफ फसल की पैदावार का आकार सीजन के लक्ष्य और पिछले साल के स्तर से काफी कम रहने की संभावना है। इससे भी बुरी बात यह है कि क्टऊके ताजा अनुमान के मुताबिक, रबी फसलों के लिए और भी चिंताजनक तस्वीर उभर रही है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान अल नीनो की स्थिति और गंभीर होने और 'बहुत गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की संभावना है। यह समय रबी फसलों की बुवाई का होता है। रबी की मुख्य फसलों में गेहूं, दालें (मुख्य रूप से चना और मसूर) और तिलहन (मुख्य रूप से रेपसीड-सरसों) शामिल हैं, और इन फसलों की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी में नमी और सर्दियों की बारिश की जरूरत होती है। बड़ी चिंता यह है कि यह 2015-16 के सीजन जैसा दोहरा झटका हो सकता है, जब देश को लगातार दो सीजन में सामान्य से कम बारिश, फसल उत्पादन में भारी गिरावट, खाने-पीने की चीजों की महंगाई और ज्यादा इंपोर्ट का सामना करना पड़ा था। खाने-पीने की चीजों की महंगाई की चिंता इस साल भी हमें खाने-पीने की चीजों की महंगाई के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। अगर पर्शियन गल्फ संकट से एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट जारी रहती है और कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक तीन अंकों (ब्रेंट वर$100 प्रति बैरल और उससे ऊपर) में बनी रहती है, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। खाद की कमी और बढ़ी हुई कीमतें खेती के हालात को और खराब कर सकती हैं। तो सरकार के पास क्या पॉलिसी विकल्प हैं? पॉलिसी बनाने वालों के लिए फूड सिक्योरिटी और महंगाई पर काबू पाना दो मुख्य प्राथमिकताएं होनी चाहिए। चीनी का एक्सपोर्ट सितंबर तक रोक दिया गया है और स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। यह पक्का करना जरूरी है कि चावल और गेहूं के बफर स्टॉक का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि आबादी के कमजोर वर्गों के लिए अच्छे अनाज की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। जब तक अगले साल तक सप्लाई सामान्य नहीं हो जाती, तब तक इथेनॉल के लिए अनाज (मक्का और चावल) के इस्तेमाल पर सख़्त रोक लगाई जानी चाहिए,

टॉयलेट की सफाई पर ध्यान जरूरी, प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों से ही होगा सुधार

स्वच्छ भारत की राह में सफाई कर्मियों का योगदान जब 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शहरों में सफाई व्यवस्था कमजोर पड़ रही है और शहर नई पहल कर रहे हैं (जैसे मुंबई की धारावी में), तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ठलअक) ने टोल प्लाजा के पास आधुनिक शौचालय बनाने की पहल शुरू की है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि रइट के शहरी हिस्से के तहत कई शहरों में बनाए गए चमकदार सार्वजनिक शौचालयों को चुपचाप हटा दिया गया और कई मामलों में, उनकी जगह स्थानीय निकायों द्वारा पुराने ढंग की सुविधाएं बना दी गईं। अ'रङ्ग र्फी - मानसून का बढ़ता खतरा, रबी फसल पर संकट आसानी से इस्तेमाल हो सकने वाले यूरिनल (पेशाबघर) का न होना, उन सर्विस प्रोफेशनल्स और गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी कमी है जो दिन भर बाहर काम करते हैं; इससे सफाई व्यवस्था के मामले में हम पीछे चले गए हैं। जब लोगों को यूरिनल नहीं मिलते, तो वे शांत सड़कों पर एकांत कोनों और खड़ी गाड़ियों की आड़ में अपनी जरूरत पूरी करते हैं; इससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। यह एक ऐसे बड़े कार्यक्रम के लिए बहुत खराब नतीजा है जिस पर 18,543 करोड़ रुपये का भारी-भरकम खर्च हुआ है। यह रकम केंद्र सरकार ने 2024-25 तक 11 सालों में पूरे देश में रइट-शहरी कार्यों के लिए जारी की थी। हालांकि रइट का दावा है कि 37,766 सार्वजनिक शौचालय मौजूद हैं, लेकिन इस बात पर बहुत कम स्पष्टता है कि आज उनमें से कितने चालू हालत में हैं और असल में इस्तेमाल हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, ठलअकटोल प्लाजा पर 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस आधुनिक शौचालयों में नए सिरे से निवेश करने की योजना बना रहा है। हाईवे का इस्तेमाल करने वालों से सफाई के मानकों को बेहतर बनाने और यूजर फीडबैक के आधार पर रखरखाव करने का वादा किया गया है। यह निश्चित रूप से उम्मीद जगाने वाला है, लेकिन अक्सर सार्वजनिक परियोजनाओं में खराब तरीके से काम करने के कारण अच्छे इरादे भी धरे के धरे रह जाते हैं। रखरखाव प्राथमिकता होनी चाहिए सार्वजनिक सफाई व्यवस्था कई वजहों से पिछड़ रही है, जिसमें सबसे बड़ी वजह शौचालयों की हालत के लिए ज़िम्मेदार किसी खास रखरखाव तंत्र का न होना है। कुछ मामलों में, शौचालय राजनीतिक विवाद का विषय बन जाते हैं, और स्थानीय प्रभावशाली राजनेता उन्हें लगवाने की इजाजत देने के बदले रिश्वत की उम्मीद भी करते हैं। हाईवे पर बने शौचालयों की हालत शायद बेहतर हो सकती है क्योंकि वे अलग-थलग होते हैं, लेकिन ठलअक मौजूदा शौचालयों के नवीनीकरण और नए शौचालयों के निर्माण, दोनों के लिए एक जैसे और देश में ही विकसित डिजाइनों की बात कर रहा है। दुर्भाग्य से, कई सार्वजनिक सुविधाओं की मौजूदा हालत भरोसा नहीं जगाती। इसके अलावा, भारत ने टॉयलेट को नए सिरे से बनाने के लिए इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई एडवांस्ड पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद फ्लशिंग को कम करना या खत्म करना, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट को अपने-आप अलग करना और बड़ी मात्रा में जमा मल को मैनेज करने के लिए हाई-टेंपरेचर डीकंपोज़िशन या पायरोलिसिस का इस्तेमाल करना है।

विरोध-उत्सव, घिनौनी संप्रभुता और आदर्श लोक की रिहर्सल की गाथा

आदर्श लोक की रिहर्सल की गाथा ह्लअगर मैं इस पर नाच नहीं सकती, तो यह मेरी क्रांति नहीं है। यह बात नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अराजकतावाद की एक मजबूत आवाज, एम्मा गोल्डमैन ने कही थी। जंतर-मंतर पर अपनी क्रांति का जश्न मनाते हुए नाचने और गाने वाले युवा भारतीयों का भी यही मकसद था। गोल्डमैन ने मशहूर बात कही थी, अमीरों के महलों के सामने प्रदर्शन करो; काम की मांग करो। अगर वे तुम्हें काम न दें, तो रोटी की मांग करो। अगर वे दोनों देने से मना कर दें, तो रोटी छीन लो। अमेरिकी सरकार ने उन्हें रेड एम्माह्व और अमेरिका की सबसे खतरनाक महिला का नाम दिया था। हालांकि कई बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों की बुराई की, लेकिन सरकार ने संयम दिखाते हुए युवा प्रदर्शनकारियों की तुलना रेड एम्मा से नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर एक दुर्लभ कदम पीछे खींचना पड़ा। जैसा कि वरिष्ठ कमेंटेटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने कहा है, यह सिर्फ़ एक मंत्री का जाना नहीं है... यह वह पल हो सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी की अजेय (कभी न हारने वाली) छवि में आखिरकार दरार आ गई हो। जश्न के तौर पर राजनीति युवा प्रदर्शनकारियों ने विरोध-प्रदर्शन को एक उत्सव और कार्निवल में बदल दिया, ठीक वैसे ही जैसे हाल के वर्षों में लैटिन अमेरिका में आदिवासी और महिला आंदोलनों ने किया है। प्रदर्शनकारियों ने संगीत, मीम्स और रील्स का इस्तेमाल नाचने और भूलने के लिए नहीं, बल्कि शासक वर्ग को चोट पहुँचाने और अपमानित करने के लिए किया। गानों, नृत्यों, मीम्स और रील्स ने उन्हें दुनिया को देखने का एक नजरिया दिया। जंतर-मंतर पर राजनीति और गाने एक-दूसरे में घुल-मिल गए। इस पीढ़ी के लिए, राजनीति सिर्फ़ राजनीति के लिए नहीं है; यह ज़िंदगी के लिए है। उनके विरोध का मकसद सिर्फ़ आकर्षित करना नहीं, बल्कि लुभाना था। प्रदर्शनकारियों ने अपने शरीर का इस्तेमाल एक राजनीतिक काम के तौर पर किया। ऐसे समय में जब दुनिया भर की सरकारें नागरिकों को दिए गए अधिकार छीन रही हैं, युवा प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर लोगों का हक जताया, न कि सिर्फ़ कारों का। न्यूयॉर्क में, अगर किसी पार्क में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो आपको स्थानीय अधिकारियों से इजाजत लेनी पड़ती है। अमेरिका के कई अन्य शहरों में, सड़क पर मार्च तभी मुफ़्त है जब उसमें 100 से कम लोग शामिल हों और वे सिर्फ़ एक लेन का इस्तेमाल करें। लंदन में, राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों को लूटपाट करने वालों की तरह ही सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। मोदी सरकार ने भी इंडिया गेट, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में विरोध-प्रदर्शनों पर रोक लगाई है। एक पीढ़ी सत्ता को चुनौती देती है जानती है कि वे ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे सलमान रुश्दी ने कुछ भी हो सकने वाला दौर₹ कहा है। रुश्दी ने यह बात अमेरिका के बारे में कही थी। वे यही बात भारत के बारे में भी कह सकते थे। उन्होंने चेतावनी दी थी, सावधान अमेरिका! यह मत सोचो कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। रुश्दी उस दौर की बात कर रहे थे जहाँ सच को हेर-फेर करके दबा दिया जाता है। एम्मा की तरह, मिलेनियल्स और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। बीजेपी नेताओं, सरकार के इशारे पर चलने वाले मीडिया और चर्चा करने वाले कुछ खास वर्गों का हमेशा से यह मानना रहा है कि नए एयरपोर्ट, सुपरहाइवे, बड़े मॉल और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना ही मानव सभ्यता के नए नैतिक ऊँचे मुकाम को तय करता है। बहुत ज्यादा प्रचारित ₹विकसित भारत₹ के सपने को एक जाल की तरह बिछाया गया है, इस उम्मीद में कि हकीकत इतनी नासमझ होगी कि उसमें फँस जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ` की अगुवाई में पहली इंस्टा क्रांति का होना यह दिखाता है कि कैसे दूसरों को दबाने वाली बहुसंख्यकवादी सोच ने लोकतंत्र को खोखला कर दिया है और कैसे कारोबार गिद्धों की दावत बन गया है। हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि भारत अब सिर्फ़ नायकों और खलनायकों से बना है। तथ्यों से रहित दो-तरफा कहानियों के कारण, भारत की राजनीति पक्षपाती डॉक्युड्रामा बन गई है। हर नई पीढ़ी को पिछली पीढ़ी के लोग दोषी ठहराते हैं, यहाँ तक कि उन पर दाग भी लगाते हैं। क्या 'बूमर्स' को बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, 'त्र्रील्ल ' वालों को निराशावादी और मिलेनियल्स को हक जताने वाला नहीं माना गया था? कई लोग त्र्रील्ल` को गैर-पेशेवर, बिना तैयारी के, स्क्रीन से चिपके रहने वाले और अक्सर इंसान होने की खुशी से दूर रहने वाले के तौर पर देखते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो उन्हें संभावित रूप से नौकरी के लायक न होने वाले तक कह दिया है। हालाँकि, आखिर में जीत की ही हुई है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की माँग पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया गया है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनके कार्यकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता₹ दिखाई दी है। दूसरे मंत्रियों ने भी प्रधान के साथ एकजुटता दिखाई है। शांतिपूर्ण विरोध की ताकत पी. बी. शेली के अनुसार, ₹कवि दुनिया के ऐसे कानून बनाने वाले होते हैं जिन्हें मान्यता नहीं मिली होती।₹ कवियों की तरह, गाने और गायक भी समाज पर गहरा असर डालते हैं

सरकार के रणनीतिक बदलाव के पीछे क्या है वजह

पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध भले ही तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और केंद्र सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगों को मानने के साथ खत्म हो गया हो, लेकिन इसे लेकर बहस निश्चित रूप से खत्म नहीं हुई है। श्रेय लेने की होड़ पहले ही शुरू हो चुकी है। राजनीतिक पसंद के आधार पर, इसे या तो सरकार की हार के रूप में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता और उदारता के प्रमाण के रूप में पेश किया जा रहा है। अ'रङ्ग र्फी - मानसून का बढ़ता खतरा, रबी फसल पर संकट हालाँकि, सच्चाई कहीं अधिक साधारण हो सकती है। यह मोदी की उदारता का कार्य नहीं था, बल्कि राज्यों में जल्द होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया एक राजनीतिक निर्णय था। अगले साल की शुरूआत में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। पंजाब को छोड़कर, बाकी सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इन राज्यों में किसी भी तरह की हार का असर 2029 के बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है, जब बीजेपी लगातार चौथी बार सत्ता में आने की कोशिश करेगी। मोदी का राजनीतिक गणित आइए स्पष्ट हों: मोदी कोई संत नहीं हैं। वह एक कठोर राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्हें हार पसंद नहीं है और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शायद ही कभी हार का सामना किया हो। पिछले पच्चीस वर्षों में, उन्हें चुनावों में वास्तव में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीन बार जीत हासिल की। उनकी जीत का सिलसिला तब और बढ़ गया जब पार्टी ने 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। वह पहले ही सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बना चुके हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1951-52 के आम चुनावों में ही अपना पहला जनादेश हासिल किया था। आधा दर्जन बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी, मोदी अपने विरोधियों के लिए एक पहेली बने हुए हैं, जो अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि उन्हें कैसे हराया जाए या उन्हें सत्ता की कुर्सी से कैसे हटाया जाए। अगर वह उतने ही चिंतित और उदार होते जितना उनके प्रशंसक मानते हैं, तो छात्रों का विरोध शायद 49 दिनों तक नहीं चलता। अधिक संभावना यह है कि अधिकारियों ने शुरू में अमेरिका स्थित एक भारतीय कार्यकर्ता द्वारा शुरू की गई व्यंग्यात्मक 'कॉकरोच जनता पार्टी' को कम करके आंका। कई लोगों ने इसे मजाक समझा, खासकर भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक विवादास्पद टिप्पणी के बाद, जिसकी व्याख्या बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करने के रूप में की गई थी। लेकिन विरोध प्रदर्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मामले के जल्द और स्वाभाविक रूप से खत्म होने के कोई आसार न दिखने और राजनीतिक समय-सीमा के करीब आने के साथ, मोदी सरकार को शायद एक बार फिर एक साधारण सी सच्चाई याद दिलाई गई: जन-आंदोलन और जनता की भावनाएं वोटरों पर ऐसे असर डाल सकती हैं जो तुरंत तो नहीं दिखते, लेकिन अक्सर वोटिंग के समय गहराई से महसूस किए जाते हैं। किसानों के आंदोलन से सीख छात्रों के आंदोलन की तुलना किसानों के उस आंदोलन से की जा सकती है जो अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक, यानी एक साल और चार महीने से ज्यादा समय तक चला था। यह मोदी सरकार के तीन विवादित कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ था और बाद में कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य (टरढ) की कानूनी गारंटी की व्यापक मांग में बदल गया। उस आंदोलन ने कई मायनों में बीजेपी के ₹अबकी बार 400 पार₹ के सपने को चकनाचूर कर दिया। आखिर में, पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ़ 240 सीटें जीत पाई और उसे अपने मौजूदा और नए सहयोगियों की मदद से सरकार बनानी पड़ी। 2019 की तुलना में बीजेपी की सीटों की संख्या में 63 सीटों की कमी आई। इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखा। 2014 में, बीजेपी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटें जीती थीं। 2019 में यह संख्या घटकर 62 हो गई और 2024 में और गिरकर 33 रह गई। अकेले इसी गिरावट ने बीजेपी को अपने दम पर बहुमत पाने से रोक दिया और उसे सहयोगियों पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर दिया। किसानों के आंदोलन की हलचल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी महसूस की गई थी। बीजेपी की सीटों की संख्या 2017 में 403 में से 312 से घटकर 2022 में 255 हो गई। पार्टी इस संदेश को समझ गई थी। भौगोलिक स्थिति भी मायने रखती है। दिल्ली के पूर्वी हिस्से से सटे और नेशनल कैपिटल रीजन (ठउफ) का एक बड़ा हिस्सा अपने दायरे में रखने वाले उत्तर प्रदेश में केंद्र के फैसलों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशीलता रहती है। इसमें यह बात भी जोड़ लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पारंपरिक रूप से संघर्षशील रहे हैं, और छात्रों के आंदोलन के दौरान राज्य के काफी युवा दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमा हुए थे, तो राजनीतिक जोखिम साफ हो जाता है। पहले एक बार मुश्किल में फँस चुकी मोदी सरकार, छात्रों के आंदोलन को चुनाव के लिए बड़ी मुसीबत नहीं बनने देना चाहती थी, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश और दूसरे अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हों। इसीलिए, पीछे हटने के फैसले को उदारता का नाम दिया गया।

स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए पहल, महाराष्ट्र में जंक फूड पर प्रतिबंध लागू

महाराष्ट्र में जंक फूड पर प्रतिबंध लागू महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने पिछले हफ़्ते बच्चों के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाया। उन्होंने अपने राज्यों में स्कूल कैंटीन और सभी स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में डीप-फ्राइड और अस्वास्थ्यकर खाने की चीजों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। इसके तहत, ल्त्र्रर फूड (यानी ज्यादा फैट या ट्रांस फैट, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थ) की बिक्री, वितरण या विज्ञापन भी नहीं किया जा सकेगा। इनमें चिप्स, वेफर्स, वड़ा, वड़ा पाव, समोसे, केक, कुछ तरह के बिस्कुट, मीठे ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह शामिल हैं, जिन्हें आम तौर पर 'जंक फूड' कहा जाता है। इन राज्यों के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें सजा दी जाएगी; महाराष्ट्र 'फूड सेफ़्टी एंड स्टैंडड्र्स (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) रेगुलेशंस, 2020' को लागू करेगा। जन-स्वास्थ्य के लिए एक समय पर उठाया गया कदम हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस सख़्ती का विरोध कर सकते हैं और परेशान परिवार - खासकर माताएं, जो बच्चों को पौष्टिक स्नैक और लंच देने के लिए पहले से ही बहुत मेहनत करती हैं - उनके लिए यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह कदम बहुत जरूरी था। महाराष्ट्र में, इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्कूलों में पढ़ने वाले दो करोड़ से ज्यादा बच्चे दिन में कम से कम एक बार स्वस्थ भोजन करेंगे और स्कूल के बाहर जंक फूड पर अपनी पॉकेट मनी खर्च करने का लालच कम होगा। स्कूलों की ज़िम्मेदारी है कि वे ऐसी चीजें बेचने वाली दुकानों की रिपोर्ट त्र्छ्अ को दें; महाराष्ट्र के त्र्छ्अ कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो स्कूल अपने परिसर में नियमों का उल्लंघन करेंगे और 50 मीटर के दायरे में ऐसी दुकानों की रिपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी मान्यता (एफि लिएशन) संबंधित बोर्ड से रद्द की जा सकती है। इसे और बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत ऊपर से देखने पर यह जरूरत से ज्यादा सख़्ती लग सकती है, लेकिन यह देखते हुए कि भारत अब बच्चों में मोटापे की एक बड़ी जन-स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहा है - जिसमें 4.1 करोड़ बच्चों का इटकज्यादा है और उनमें से 1.4 करोड़ बच्चे 5 से 19 साल की उम्र के हैं - यह कदम जरूरी था। ज्यादातर मोटे बच्चे शहरी या अर्ध-शहरी इलाकों में रहते हैं, जहाँ शारीरिक गतिविधियों के लिए कम जगह होती है और सुस्त जीवनशैली को बढ़ावा मिलता है; जंक फूड इस समस्या को और बढ़ाते हैं। असल में, दूसरे राज्यों को भी महाराष्ट्र और कर्नाटक की राह अपनानी चाहिए। 2040 तक भारत में 56 मिलियन बच्चों के मोटापे से जूझने का अनुमान गंभीर सोच और कार्रवाई की मांग करता है।

CJP का विरोध: जब अपशब्दों का इस्तेमाल बगावत की निशानी बन जाए

अपशब्दों का इस्तेमाल बगावत की निशानी बन जाए दिल्ली के जंतर-मंतर पर ठएएळ पेपर लीक के आरोपों को लेकर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन को जवाबदेही की मांग के लिए याद किया जाना चाहिए था। परीक्षा में बार-बार हो रही गड़बड़ियों पर अपना गुस्सा जाहिर करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने के लिए हजारों छात्र इकट्ठा हुए। बड़ी संख्या में युवा महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया, जो छात्र आंदोलन के बदलते स्वरूप को दशार्ता है। प्रदर्शन का एक और पहलू भी काफी चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कई प्रदर्शनकारियों, जिनमें युवा महिलाएं भी शामिल थीं, को भाषणों और इंटरव्यू के दौरान भद्दी और अपशब्दों वाली भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया। बाद में उनमें से कुछ ने माफी मांगते हुए वीडियो पोस्ट किए और कहा कि उन्होंने गुस्से में या आवेश में आकर ऐसा कहा था, या उन्हें लोगों की तीखी प्रतिक्रिया का अंदाजा नहीं था। यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है: युवा महिलाओं के बीच अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? क्या यह जेंडर से जुड़े बदलते नियमों का संकेत है, सोशल मीडिया का असर है, या इस बात का सबूत है कि सार्वजनिक बातचीत का तरीका ही ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है? अपशब्दों की पितृसत्तात्मक जड़ें भाषा और जेंडर पर अध्ययन करने वाले विद्वानों का दशकों से यह तर्क रहा है कि भारतीय भाषाओं में ज्यादातर अपशब्द पितृसत्तात्मक सोच से गहराई से जुड़े हैं। सबसे कठोर अपमान महिलाओं के शरीर, उनकी सेक्सुअलिटी या पारिवारिक रिश्तों को निशाना बनाते हैं। पारंपरिक रूप से, पुरुष अपना दबदबा कायम करने या अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए दूसरे पुरुषों के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये अपशब्द शायद ही कभी सिर्फ़ महिलाओं के बारे में होते थे। इनका संबंध सत्ता या ताकत से होता था। अ'रङ्ग र्फी - विरोध-उत्सव, घिनौनी संप्रभुता और आदर्श लोक की रिहर्सल की गाथा यही वजह है कि कई नारीवादी विद्वानों ने अपशब्दों को पितृसत्तात्मक नियंत्रण का एक जरिया बताया है। महिलाओं का शरीर पुरुषों की इज्जत का प्रतीक बन गया और उनका अपमान करना दूसरे पुरुष को नीचा दिखाने का एक तरीका बन गया। यह भाषा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को दशार्ती थी जिसमें महिलाओं को पुरुष की पहचान का ही एक हिस्सा माना जाता था। आज जो चीज बदलती दिख रही है, वह भाषा या शब्द नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। 'जेनरेशन`' का एक वर्ग अपशब्दों को जेंडर-न्यूट्रल (स्त्री-पुरुष से परे) मानने लगा है। युवा महिलाएं अब ऐसे शब्दों और मुहावरों का इस्तेमाल करती हैं जो कभी सिर्फ़ पुरुषों के हॉस्टल, राजनीतिक रैलियों, खेल के मैदानों और दफ़्तरों तक ही सीमित थे। कई लोगों के लिए, यह भाषा अश्लीलता के बजाय आत्मविश्वास और बराबरी की निशानी मानी जाती है। इसके पक्ष में अक्सर एक सीधा-सा तर्क दिया जाता है। अगर पुरुष बिना किसी नैतिक आलोचना के अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो महिलाओं के लिए अलग पैमाने क्यों होने चाहिए? इस नजरिए से बराबरी का मतलब है भाषा के इस्तेमाल की वैसी ही आजादी मिलना। इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाने में दम है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा सख़्त नैतिक जांच का सामना नहीं करना चाहिए। हालाँकि, समान आजादी का मतलब यह जरूरी नहीं है कि अभिव्यक्ति के हर तरीके की तारीफ ही की जाए। महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई शब्दावली, महिलाओं के इस्तेमाल करने से ही अपनी महिला-विरोधी जड़ें नहीं खो देती। बोलने वाला बदलने पर भी शब्द वही रहते हैं। सोशल मीडिया और सांस्कृतिक प्रभाव सोशल मीडिया ने इस बदलाव को तेज कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म गुस्से, टकराव और चौंकाने वाली बातों को बढ़ावा देते हैं। सोच-समझकर दी गई दलील पर शायद ही किसी का ध्यान जाए, जबकि आक्रामक नारा या गाली-गलौज वाली बात कुछ ही घंटों में वायरल हो सकती है। युवा यूजर्स जल्दी ही समझ जाते हैं कि विवाद से ज्यादा लोग उन्हें देखेंगे। ऐसे माहौल में, भाषा बातचीत का जरिया न रहकर एक दिखावा या परफॉर्मेंस बन जाती है। लोकप्रिय संस्कृति ने भी इस चलन को मजबूत किया है। फि ल्में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, स्टैंड-अप कॉमेडी और रैप म्यूज़िक असलियत दिखाने के नाम पर गाली-गलौज वाली भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। लगातार ऐसी भाषा सुनने से गालियों से जुड़ा बुरा भाव धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। 'जेनरेशन`' ऐसे माहौल में बड़ी हुई है जहाँ गाली-गलौज को स्वाभाविक, मजेदार या फैशनेबल माना जाता है। समाजशास्त्री बताते हैं कि गाली देना सिर्फ़ गुस्से का इजहार नहीं है; यह पहचान और किसी समूह का हिस्सा होने का भी संकेत है। दोस्तों के कई समूहों में, गाली देना आत्मविश्वास, असलियत और मजबूती की निशानी माना जाता है। जो लोग ऐसी भाषा से बचते हैं, उन्हें डरपोक या जमाने से कटे हुए समझा जा सकता है। यह दबाव युवा पुरुषों और महिलाओं, दोनों पर असर डालता है। इसलिए, बहस सिर्फ़ महिलाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पुरुष ज्यादातर गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी समाज इसे शायद ही कभी सांस्कृतिक संकट मानता है। जब महिलाएं ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि यह महिलाओं से जुड़ी पारंपरिक उम्मीदों को चुनौती देता है।

हेलीकॉप्टर सीधे ज्वालामुखी में जा गिरा, उबलते लावे के बीच कैसे बिताई पूरी रात?

हवा में उड़ते हुए किसी विमान का सीधे धधकते ज्वालामुखी में गिर जाना अपने आप में एक भयावह हादसा है. लेकिन जरा सोचिए, क्या उस विमान में सवार लोगों के साथ इससे भी ज्यादा डरावनी घटना हो सकती है?

हाँ, बिल्कुल हो सकती है.

कल्पना कीजिए कि हादसे के बाद पूरी रात आपको उसी ज्वालामुखी के क्रेटर में बितानी पड़े, जहां आपके पैरों के ठीक नीचे उबलता हुआ लावा बह रहा हो. यह किसी भी विमान दुर्घटना से कहीं ज्यादा भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा.

यह कहानी नवंबर 1992 की है.

हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों 'टाइटैनिक' और 'टर्मिनेटर 2' के विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) टीम के सदस्य क्रिस डट्टी अमेरिका के हवाई राज्य के 'बिग आइलैंड' पर एक नई हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे थे.हेलीकॉप्टर में उनके साथ पायलट ग्रेग हॉस्किंग और कैमरा असिस्टेंट माइक बेनसन भी मौजूद थे. घने भाप के बादलों के बीच उड़ान भरते समय उनका हेलीकॉप्टर बदकिस्मती से एक चट्टान से टकरा गया. अगले ही पल इंजन पूरी तरह बंद हो गया और नियंत्रण खो चुका हेलीकॉप्टर सीधे धधकते ज्वालामुखी के क्रेटर में जा गिरा.

क्रिस डट्टी ने बाद में उस पल को याद करते हुए कहा, ₹हम हेलीकॉप्टर से फिल्म 'सिल्वर' के क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग कर रहे थे. नजारा बेहद शानदार था. किलाउएआ ज्वालामुखी से निकलता उबलता हुआ लावा सीधे समंदर के पानी से मिल रहा था और उससे उठने वाला सफेद धुएं का विशाल गुबार आसमान तक फैल रहा था. उन्होंने कहा, उस वक्त मैंने मन ही मन सोचा था, 'यकीन नहीं होता कि मुझे इस शानदार काम के लिए पैसे मिलते हैं. दुनिया में इससे बेहतरीन नौकरी शायद ही कोई होगी.'क्रिस डट्टी ने बताया, वह शनिवार की सुबह थी. एक बड़ा तूफान तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था, इसलिए हमारे पास शूटिंग पूरी करने के लिए सिर्फ.दो-तीन घंटे का समय था.उन्होंने कहा कि फिल्म के उस दृश्य में मुख्य कलाकारों को ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ते हुए धीरे-धीरे दृश्य से गायब होते दिखाना था.

क्रिस के मुताबिक, माइक कैमरे में रिकॉर्ड हुए शॉट को स्क्रीन पर देखकर बोला, 'हम इससे भी बेहतर शॉट ले सकते हैं.' और ठीक उसी पल सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया.क्रिस डट्टी बताते हैं, जब हम दोबारा ज्वालामुखी की ओर बढ़े तो उससे धुएं के बड़े-बड़े गुबार निकल रहे थे. जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, धुआं इतना घना होता गया कि हमारे सामने कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया. तभी अचानक हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा जोर-जोर से हिलने लगा.

हे भगवान! पायलट ग्रेग हॉस्किंग घबराकर चिल्लाए.जब मैंने ऊपर देखा तो चारों तरफ सिर्फ.सफेदी ही सफेदी थी, जैसे हम बादलों के भीतर हों. तभी ग्रेग फिर चिल्लाए, 'हम गिरने वाले हैं!'क्रिस बताते हैं कि हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड एक सीधी खड़ी चट्टान से टकरा गए और टूटकर बिखर गए. इसके बाद हेलीकॉप्टर पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा और तेजी से नीचे गिर गया.

टक्कर इतनी भीषण थी कि ग्रेग और कैमरा असिस्टेंट माइक बेनसन अपनी सीटों से उछल गए. हेलीकॉप्टर ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वे बाहर की ओर जा गिरे. ग्रेग के सिर में गंभीर चोट लगी थी और आंख के पास गहरा घाव होने के कारण लगातार खून बह रहा था. हम किसी तरह हेलीकॉप्टर से बाहर निकले और चारों ओर देखा. हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड गायब थे और उसका पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो चुका था.वहां जहरीली गैसों की मात्रा इतनी अधिक थी कि सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा था. सल्फर की तीखी गैस से सीने में जकड़न और आंखों में तेज जलन हो रही थी.कुछ देर बाद जब शुरूआती सदमे से उबरे तो मैंने चारों ओर देखा और पूछा, ₹क्या हम किसी ज्वालामुखी के अंदर फंस गए हैं?

ग्रेग ने जवाब दिया, हां।

मैंने अगला सवाल किया, क्या किसी को पता है कि हमारे साथ हादसा हो गया है? ज्वालामुखी के भीतर कैद जिस क्रेटर में हम गिरे थे, वह किसी फुटबॉल मैदान से कई गुना बड़ा और बेहद गहरा था.हम ज्वालामुखी की ऊपरी सतह से करीब 100 मीटर नीचे फंसे हुए थे. किसी भी तरह वहां से बाहर निकलना जरूरी था.हमने ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह बेहद कठिन था. लावा के ठंडा होकर बने पत्थर हल्का-सा दबाव पड़ते ही टूटकर नीचे गिर जाते थे. उनकी धार चाकू की तरह तेज थी. उन पर चलना ऐसा था मानो टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर रेंग रहे हों.मैं करीब आधी चढ़ाई तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ना लगभग असंभव लगने लगा.मैंने नीचे खड़े माइक और ग्रेग से जोर से कहा, ₹मैं यहीं रुक रहा हूं.

हजारों किलोमीटर दूर चल रही जंग की आंच यूपी के देवरिया तक कैसे पहुंच गई?

पहली बार जब मेरा बेटा घर से जा रहा था, गौरीबाजार स्टेशन पर मुझे गले लगाया, पीठ थपथपाई और दोनों गालों को चूमा. मैंने भी अपने बेटे को गले लगाया. आंखें भर आईं उस समय. बेटा बोला था कि पापा अब चिंता नहीं करना है, मैंने कदम बढ़ा दिया है.यह कहते हुए कौशल निषाद की आंखें भर आती हैं. उन्हें नहीं मालूम था कि जिस बेटे को वे बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ पहली बार कार्गो जहाज पर नौकरी के लिए विदा कर रहे हैं, वह फिर कभी घर लौटकर नहीं आएगा.उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के करमेल गांव का यह परिवार शोक में डूबा है. परिवार अपने 22 वर्षीय बेटे अभिषेक निषाद के पार्थिव शरीर के वापस आने का इंतजार कर रहा है. अभिषेक निषाद की समुद्र में यह पहली नौकरी थी.भारतीय समय के अनुसार, 19 जुलाई की रात यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हुए कार्गो जहाज पर मिसाइल हमला हुआ जिसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई. इसमें चार भारतीय नाविक भी शामिल थे.मालवाहक जहाजों को निशाना बनाए जाने की निंदा करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने 20 जुलाई को जारी एक बयान में कहा कि एमवी गोल्डन लियो पर ओडेसा बंदरगाह से रवाना होने के दौरान हमला हुआ. घटना के समय जहाज पर चालक दल के 17 सदस्य सवार थे, जिनमें पांच भारतीय नागरिक शामिल थे.मंत्रालय के मुताबिक, इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक भारतीय नागरिक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है.अभिषेक निषाद कार्गो जहाज पर ओएस (ऑर्डिनरी सीमैन) पद पर कार्यरत थे. आमतौर पर मर्चेंट नेवी में करियर की शुरूआत ओएस पद से होती है.अभिषेक जहाज पर साफ-सफाई, रखरखाव, निगरानी और संचालन से जुड़ा काम करते थे.

इस काम के लिए कंपनी अभिषेक को 300 अमेरीकी डॉलर (करीब 28 हजार रुपये) दे रही थी.

परिवार के अनुसार, जब जहाज पर मिसाइल का हमला हुआ तो उससे कुछ समय पहले तक अभिषेक की व्हाट्सऐप के जरिए पिता कौशल निषाद से बात हो रही थी. निषाद बीबीसी न्यूज हिन्दी को बताते हैं, ₹बेटे से मेरी अंतिम बात 19 जुलाई की शाम 05:18 बजे (भारतीय समय के अनुसार) हुई थी. उसने वॉयस नोट में मैसेज भेजा था कि वह ड्यूटी पर है, शाम में बात करेगा. उसके बाद से उसका इंटरनेट बंद हो गया.रात भर मैं, उसकी मां और दोनों बहनें इंतजार करती रहीं लेकिन सुबह तक कोई रिप्लाई नहीं आया. सुबह बेटी ने इंटरनेट पर देखा तो बताया कि मिसाइल हमले में जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है.कौशल निषाद और अनीता देवी की तीन संतानों में अभिषेक निषाद इकलौते बेटे थे. उनसे बड़ी बहन साधना निषाद और छोटी बहन आराधना निषाद हैं.कौशल निषाद बीबीसी न्यूज हिन्दी से कहते हैं, ₹मेरा बेटा मुंबई से तुर्की गया और वहां से 11 जून को नौकरी ज्वाइन कर ली. वहीं से अनाज लादकर जहाज यूक्रेन गया. यूक्रेन में बमबारी शुरू हो गई.

यमन के पास हमले में भारतीय झंडे वाला जहाज डूबा, यमन ने हूती विद्रोहियों को बताया ज़िम्मेदार

अधिकारियों ने बताया कि यमन के तट के पास एक प्रोजेक्टाइल की चपेट में आने के बाद भारतीय झंडे वाला एक जहाज पलट गया और डूब गया.भारत के जहाजरानी मंत्री सबानंद सोनोवाल ने कहा कि एमएसवी फैज नूरे ओलिया पर सवार सभी 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. इनमें 13 भारतीय नागरिक थे.सोनोवाल ने इस 'बिना उकसावे के किए गए हमले' की निंदा की और कहा कि क्षेत्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जहाज पर हमला किसने किया. लेकिन सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों पर आरोप लगाए हैं.

यह लाल सागर में जहाजों पर हुए हालिया हमलों की कड़ी में ताजा मामला है. इसी साल फरवरी में ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने के बाद कुछ टैंकर इस वैकल्पिक समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं.बाद में भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हो रहे हमलों को 'गहरी चिंता का विषय' बताया.विदेश मंत्रालय ने कहा, ₹क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में मुक्त और निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए.

यमनी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

सऊदी समर्थित यमन सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ₹यह हमला हूती आतंकवादी मिलिशिया की लगातार जारी आपराधिक गतिविधियों और हमलों की कड़ी का हिस्सा है इन गतिविधियों में शहरों को निशाना बनाना, हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों पर बमबारी करना, निर्यात बाधित करना और यमन के लोगों को आय के महत्वपूर्ण स्रोतों से वंचित करना शामिल है.मंत्रालय के अनुसार, इससे हूती तख्तापलट के कारण पैदा हुई मानवीय त्रासदी और गंभीर हो गई है.हूती समूह लाल सागर, बाब अल-मंदब स्ट्रेट और अदन की खाड़ी में बंदरगाहों और समुद्री नौवहन के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है. साथ ही वह आर्थिक और व्यापारिक हितों को भी ऐसे तरीके से प्रभावित कर रहा है जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता कमजोर पड़ रही है.फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद से क्षेत्र के कई समुद्री व्यापार मार्ग प्रभावित हुए हैं.इसके बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जो दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन मार्गों में से एक है. इसका वैश्विक तेल कीमतों पर बड़ा असर पड़ा है.सऊदी अरब से तेल लेकर आने वाले कुछ जहाज लाल सागर के वैकल्पिक समुद्री मार्ग से गुजर रहे थे, लेकिन हाल में यमन के हूती लड़ाकों द्वारा सऊदी टैंकरों पर किए गए हमलों ने क्षेत्र में जोखिम और बढ़ा दिया है.

युवाओं का गुस्सा पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्यों बन गया है?

प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र बार-बार लीक होने से नाराज जेन जी के प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को पिछले महीने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा.उनके पद छोड़ने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल संकट से उबरने में मदद मिली है, लेकिन युवाओं की नाराजगी को नियंत्रित रखना उनकी सरकार के लिए लंबे समय तक एक बड़ी चुनौती बना रह सकता है.पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों में अभियुक्तों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की घोषणा की और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नंदन नीलेकणि को सरकारी प्रयास की अगुवाई सौंप दी.लेकिन युवाओं की चिंता को कम करने के लिए इससे कहीं अधिक व्यापक प्रयास की जरूरत पड़ सकती है. युवाओं का कहना है कि उनका ऐसी व्यवस्था से धैर्य टूट रहा है, जो उन्हें नौकरियों के अवसर या ऐसा शिक्षा तंत्र नहीं दे पा रही जो उन्हें ढंग के रोजगार दिला सके.अर्थशास्त्री और 'इंडिया आउट ऑफ वर्क: रीथिंकिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी' नामक नई किताब के लेखक संतोष मेहरोत्रा ने बीबीसी से कहा, ₹पिछले 10 सालों में लेबर मार्केट की हालत बहुत तंग हो गई है. गैर-कृषि क्षेत्र की नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं और वास्तविक मजदूरी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है.उन्होंने कहा, भारत एक साथ दो समस्याओं का सामना कर रहा है. अर्थव्यवस्था ढांचागत रूप से कमजोर है, इसलिए श्रम की मांग नहीं बढ़ रही. और हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि वह ऐसे नए वर्कर तैयार नहीं कर पा रही जो रोजगार के काबिल हों.बुनियादी ढांचे पर भारी सरकारी खर्च से जीडीपी में तेज वृद्धि हुई. और यह अब तक भारत की असमान आर्थिक वृद्धि को लेकर होने वाली आलोचना के लिए सरकार का मुख्य कवच रही है.लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले महीने की उथल-पुथल शिक्षा संकट और बढ़ती युवा बेरोजगारी का स्पष्ट संकेत है और सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेश कर सकती है.

मेहरोत्रा के अनुसार, ₹देश में सीधे नकदी हस्तानांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर-डीबीटी) समेत शुरू की गईं कई कल्याणकारी योजनाएं, इस बात का संकेत हैं कि सरकार ने कम से कम निजी स्तर पर इस समस्या को पहचान लिया है.

लेकिन इसे ठीक करने का काम बहुत बड़ा है. भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसमें 15 से 29 साल की उम्र के 36 करोड़ से अधिक लोग शामिल हैं.पिछले दो दशकों में शिक्षित होने वालों की संख्या काफी बढ़ी है और निजी कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है.

हालांकि, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट' के अनुसार, ₹शिक्षा से रोजगार की ओर पड़ाव एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, खासकर ग्रेजुएट्स के लिए.युवाओं में बेरोजगारी की दर अधिक उम्र के लोगों की तुलना में लगभग चार गुना अधिक है और दुनिया के औसत से काफी अधिक है.यह समस्या नई नहीं है. पिछले 25 सालों से ग्रैजुएट्स में बेरोजगारी दर 35-40% के आसपास बनी हुई है.लेकिन भारत की जनसंख्या वृद्धि या लेबर फोर्स में आने वाली आबादी के बढ़ते आकार और बेहतर शैक्षिक परिणामों के कारण हाल के सालों में यह समस्या और भी बढ़ गई है.साल 1983 में, 20 से 29 वर्ष की उम्र वर्ग के लोगों में से 4% ग्रैजुएट थे, और उनमें से 13% बेरोजगार थे. 2023 में, 28% ग्रैजुएट थे और उनमें से 67% बेरोजगार थे.शिक्षा की गुणवत्ता रोजगार की काबिलियत को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, जबकि ग्रैजुएट लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी के बावजूद उसी अनुपात में रोजगार में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है.रिपोर्ट में पाया गया, ₹2004-05 और 2023 के बीच, जहां हर साल लगभग 50 लाख ग्रैजुएट जुड़े, वहीं केवल लगभग 28 लाख युवाओं को ही रोजगार मिला और वेतनभोगी रोजगार पाने वालों का हिस्सा और भी कम था. इससे ग्रैजुएट बेरोजगारी में वृद्धि हुई और आमदनी में वृद्धि दर धीमी हो गई.रिपोर्ट के अनुसार, ग्रैजुएट या पोस्ट ग्रैजुएट लोगों में से केवल 3.7% को ही उच्च स्तर का रोजगार मिला और 7% से भी कम को परमानेंट सैलरी वाली नौकरियां मिलीं. मेहरोत्रा कहते हैं, छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों (एसएमई) के में तत्काल सुधार से निश्चित रूप से कुछ नौकरियां पैदा हो सकती हैं. क्योंकि 'नोटबंदी' और जीएसटी के कारण नए रोजगार पूरी तरह से ठप हो गए.हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग को फिर से ज़िंदा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति के बारे में सोचने की जरूरत होगी.उनके अनुसार, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी साल 2015 में 17% से घटकर मौजूदा समय में 14% हो गई है. और मैन्यूफैक्चरिंग में रोजगार 2015 के बाद पांच सालों तक गिरा और अब जाकर उन स्तरों से थोड़ा ऊपर चढ़ा है.मेहरोत्रा का कहना है कि इस हीच 2020 के बाद कृषि क्षेत्र में कुल रोजगार में वास्तव में 8 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जो अप्रत्यक्ष बेरोजगारी का स्पष्ट संकेत है.ऐसा इसलिए है क्योंकि तेजी से औद्योगीकरण वाली अर्थव्यवस्था में लेबर आमतौर पर कृषि छोड़कर सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसा कि दुनिया भर में देखा जाता है.इन सभी चुनौतियों में एआई के आ जाने से भी जटिलता आ गई है क्योंकि सॉफ़्टवेयर जैसे प्रमुख रोजगार पैदा करने वाले उद्योगों का व्यावसायिक मॉडल तीन दशकों से भारतीय मध्यम वर्ग के सपने की जान रहा है.वॉल स्ट्रीट बैंक गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में खेती बारी के अलावा जो नौकरियां हैं उनमें 8-12% नौकरियां एआई की वजह से कम हो सकती हैं और इसके असर अभी से दिखने लगे हैं.भारत की सबसे प्रमुख स्टाफिंग एजेंसियों में से एक, टीम लीज डिज़िटल की सीईओ नीति शर्मा के अनुसार, हाल के महीनों में आईटी क्षेत्र में नई नौकरियों की रफ़्तार 10 फीसदी से कम ही रही.टेंपरेरी ठेका प्रथा बढ़ी है, सैलरी सालों से स्थिर बनी हुई है और नॉलेज आधारित नौकरियां जिन्हें भारतीय ग्रैजुएट दो दशक पहले आसान मानते थे, अब उतनी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं.

'भारत के लिए खेलना है तो कुछ मायने नहीं रखता': ये कहने वाले जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी भारतीय टीम में चुने गए

जम्मू-कश्मीर के क्रिकेट खिलाड़ी आकिब नबी भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जल्द ही डेब्यू कर सकते हैं.दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के घायल होने के बाद दो टेस्ट मैचों के श्रीलंका दौरे के लिए टीम में आकिब को शामिल किया गया है.इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सिरीज के दौरान बाएं घुटने की चोट से बुमराह अभी पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर रखा गया है.भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि आकिब नबी को पहली बार भारतीय सीनियर टीम में जगह मिली है.

आकिब नबी का शानदार प्रदर्शन

दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज आकिब नबी ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. बीते दो रणजी ट्रॉफी सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कुल 104 विकेट हासिल किए थे.साल 2025-26 के रणजी सीजन में उन्होंने 60 विकेट झटके और जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई.इसके अलावा वह हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया-ए टीम का भी हिस्सा थे, जहां उन्होंने दो फर्स्ट-क्लास मैचों में छह विकेट अपने नाम किए.अगर आकिब नबी टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हैं तो वो जम्मू-कश्मीर के पहले टेस्ट क्रिकेटर बन जाएंगे.

आकिब नबी ने साल 2020 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक 43 फर्स्ट क्लास मैचों में 162 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट आंकड़ा 24 रन देकर सात विकेट है.

फर्स्ट क्लास में आकिब ने चार विकेट सात बार, पांच विकेट 16 बार और 10 विकेट चार बार लिए हैं. इसके अलावा उन्होंने बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाते हुए 999 रन बनाए हैं.

आईपीएल में नहीं दिखा करिश्मा

बीते साल दिसंबर में आईपीएल की नीलामी में आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स ने आठ करोड़ 40 लाख रुपये देकर अपनी टीम में शामिल किया था.हालांकि, उनका आईपीएल करियर कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने इस साल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ डेब्यू किया था.इसके अलावा उन्होंने इस साल के आईपीएल सीजन में कुल पांच मैच खेले लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए. हालांकि, उनकी गेंदबाजी काफी किफायती थी और उन्होंने ज्यादा रन नहीं लुटाए.

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में जन्मे आकिब नबी बहुत ही पक्के इरादे वाले क्रिकेटर हैं. पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, इस कारण घर में बहुत सुविधाएं नहीं थीं. यही नहीं घर का सबसे करीबी क्रिकेट मैदान 54 किलोमीटर दूर श्रीनगर में था.

एक स्थानीय अखबार ने जब उनसे शुरूआत में हुई दिक्कतों के बारे में पूछा था, तो उनका कहना था, ₹आपका लक्ष्य अगर भारत के लिए खेलना है तो यह सब मायने नहीं रखता है. आपके पास संसाधन सीमित हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आप बहाने नहीं बना सकते हैं. मेरा लक्ष्य भी टीम इंडिया की जर्सी पहनना है.परवेज रसूल भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले खिलाड़ी थे, उनके बाद उमरान मलिक भी सीमित ओवर्स में भारत के लिए खेल चुके हैं.

परवेज रसूल को खेलते देखकर ही आकिब की भी क्रिकेट खेलने की इच्छा मन में जागी.

आकिब नबी के टीम इंडिया में सिलेक्शन पर परवेज रसूल ने एक्स पर लिखा है- ₹जो आपके लिए बना है, वह आपको ढूंढ ही लेगा. कोई भी रिजेक्शन या अनदेखी आपकी किस्मत नहीं बदल सकती. आकिब नबी, इंडियन टेस्ट टीम में आपके चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई. अल्लाह आपको लगातार सफलता, अच्छी सेहत और कई यादगार कामयाबियां दे. हमेशा की तरह हमें गर्व महसूस कराते रहें.

उमरान मलिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में आकिब नबी को भारतीय टेस्ट टीम में सिलेक्ट होने पर बधाई दी है.आकिब नबी ने राज्य की अंडर-19 टीम के लिए कई बार ट्रायल दिए. बहुत मशक्कत के बाद ही वह टीम में जगह पा सके.आकिब ने 2018 में लिस्ट ए में पदार्पण किया और इसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखा. वह बीते साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी पेस गेंदबाजी की धाक जमाने में सफल रहे.उन्होंने 7.41 की इकोनॉमी रेट से 15 विकेट निकाले. वहीं रणजी ट्रॉफी की 9 पारियों में 29 विकेट लेने में सफल रहे.वह दलीप ट्रॉफी में पश्चिम क्षेत्र के खिलाफ उत्तर क्षेत्र के लिए हैट्रिक भी ले चुके हैं. उन्होंने चार गेंदों में चार विकेट लिए थे. इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने 1979 में और साईराज ने 2001 में हैट्रिक ली थी.आकिब के गेंदबाजी कमाल से जम्मू-कश्मीर इस साल रणजी ट्रॉफी में पहली बार दिल्ली को हराने में सफल रही. इस जीत में उन्होंने पांच विकेट हासिल किए थे.

आकिब नबी के भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में चुने जाने के बाद उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है.केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से सांसद जितेंद्र सिंह ने आकिब नबी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा है, ₹खेल को लेकर आपकी लगन और जुनून ने आपको यह गर्व का पल दिलाया है.गौरव गुप्ता ने एक्स पर लिखा, आखिरकार, किसी को घरेलू क्रिकेट में उसकी मेहनत का इनाम मिला है. आकिब नबी, इंडिया (क्रिकेट टीम) में पहली बार चुने जाने पर बहुत-बहुत बधाई.नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने आकिब नबी को एक्स पर बधाई दी है.

उन्होंने लिखा, ₹बारामूला एक्सप्रेस आकिब नबी डार को इंडियन टेस्ट टीम में पहली बार चुने जाने पर बधाई. उनका टेस्ट टीम में चुना जाना इस बात को पक्का करता है कि कश्मीर में बहुत टैलेंट है. यह उनकी कड़ी मेहनत और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का सही इनाम है.

सशक्त बचपन, समृद्ध छत्तीसगढ़

रायपुर। किसी भी राज्य की वास्तविक प्रगति उसके बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से मापी जाती है। छत्तीसगढ़ ने इसी सोच को आधार बनाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी नीतियों और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सक्रिय नेतृत्व में प्रदेश में बच्चों के पोषण, संरक्षण और भविष्य निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आईसीडीएस, मिशन वात्सल्य, पोषण अभियान और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन ने राज्य को बाल विकास के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है।। प्रदेश में 11 हजार 490 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम और आकर्षक बनाने का कार्य तेजी से जारी है। इन केंद्रों में बिल्डिंग एज लर्निंग एड (इंछअ) पेंटिंग, पोषण वाटिका, खेल एवं शिक्षण आधारित गतिविधियों जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे बच्चे सीखने के साथ आनंदमय वातावरण में विकसित हो सकें। मनरेगा अभिसरण के माध्यम से 2 हजार 337 नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण को स्वीकृति मिली है। वहीं पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 191 नए आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा चुके हैं। नियद नेल्ला नार 2.0 के तहत 10 जिलों में 12 हजार 964 आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकताओं की संख्या 51 हजार 45 से बढ़कर 52 हजार 258 तथा सहायिकाओं की संख्या 44 हजार 826 से बढ़कर 51 हजार 548 हो गई है, जिससे सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार आया है। कुपोषण पर प्रभावी प्रहार छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों में कुपोषण कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के अनुसार 0-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग में 7.82 प्रतिशत की कमी, वेट में 4.36 प्रतिशत की कमी, अंडरवेट में 2.76 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दिसंबर 2023 में जहां बौनापन की दर 30.27 प्रतिशत थी, वह जून 2026 तक घटकर 22.45 प्रतिशत रह गई। यह उपलब्धि पोषण प्रबंधन, नियमित मॉनिटरिंग, सामुदायिक सहभागिता और आंगनबाड़ी आधारित सेवाओं के प्रभावी संचालन का परिणाम है। पोषण अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन राष्ट्रीय पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान छत्तीसगढ़ ने देशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य प्रति आंगनबाड़ी गतिविधियों में प्रथम स्थान पर रहा। अप्रैल 2025 के पोषण पखवाड़ा में भी छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया।प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर 2025 के पोषण माह के दौरान 71 हजार 887 गतिविधियां और अप्रैल 2026 के पोषण पखवाड़ा में 34 लाख 93 हजार 474 गतिविधियां आयोजित की गईं। साथ ही स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए रेडी टू ईट इकाइयों की स्थापना की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल शुरू हो चुकी है।

जहाँ कभी पानी की थी चिंता, आज हर मौसम में जीवन का आधार बना जल स्त्रोत

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण को जनभागीदारी और ग्रामीण विकास से जोड़कर लागू की जा रही विकसित भारत जी-राम-जी योजना दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बन रही है। सूरजपुर जिले के ओड़गी विकासखंड के ग्राम पंचायत कालामांजल की सफलता इस बात का प्रेरक उदाहरण है कि योजनाबद्ध जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता से किसी गाँव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती हैं।इतिहास कालामांजल कभी ऐसा गाँव था जहाँ बारिश का अधिकांश पानी बह जाता था और गर्मी आते-आते जल स्त्रोत सूखने लगते थे। पेयजल, मवेशियों के लिए पानी और खेती-किसानी जैसी आवश्यकताओं के लिए ग्रामीणों को लंबे समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पानी की कमी यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण को ग्रामीण समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इसी सोच के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर कंटूर ट्रेंच और गेबियन चेक डैम का निर्माण कराया गया। इन संरचनाओं ने वर्षा जल को रोककर जमीन में समाहित करने का प्रभावी कार्य किया। साथ ही मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण हुआ और जंगल से आने वाला कचरा डैम तक पहुँचने से पहले ही रुकने लगा। इससे जल स्त्रोत न केवल संरक्षित हुए, बल्कि अधिक स्वच्छ और सुरक्षित भी बने। ग्राम के निवासी श्री मनोहर सिंह बताते हैं कि पहले गर्मी के दिनों में पानी की तलाश ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी। मवेशियों को पानी पिलाना और खेती करना दोनों ही कठिन हो जाता था। अब वही जल स्त्रोत पूरे वर्ष उपयोग में आ रहा है। ग्रामीण इस जल का उपयोग पेयजल, स्नान, कपड़े धोने, मवेशियों को पानी पिलाने और मत्स्य पालन जैसे कार्यों में कर रहे हैं।

बलौदाबाजार में महानगरों की तर्ज पर बिछेगी पाइपलाइन

बलौदाबाजार। महानगरों की तर्ज पर अब बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के निवासियों को भी रसोई गैस सिलेंडरों के झंझट से मुक्ति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा 'सिटी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट' के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में जिलेवासियों को सीधे पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित और निर्बाध प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आपूर्ति मिलेगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना की प्रगति को लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को जिला कार्यालय में एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति का जायजा लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करें और निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें, ताकि आम नागरिकों को जल्द से जल्द इस आधुनिक सुविधा का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि पाईप लाइन बिछाने में गड्ढा खोदने के लिये लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग अथवा पंचायत से एनओसी की जरुरत होने पर शीघ्र जारी किया जाए। प्रोजेक्ट के प्रतिनिधियों ने बताया कि पाईप लाईन बिछाने कार्य रायपुर से शुरू कर दिया गया है जो जिले के सिमगा तक पहुंच गया है।वर्तमान में विकासखण्ड सिमगा के ग्राम केसदा में काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पीएनजी का कनेक्शन पाईप लाईन के आस पास के औद्योगिक प्रतिष्ठान, स्कूल, अस्पताल व शहरों में दिया जाएगा। पाईप लाइन घर के सामने से गुजरेगी जिसमें बीच- बीच में कनेक्शन बॉक्स रहेगा जहां से घर के रसोई तक कनेक्शन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि पीएनजी बहुत ही सुरक्षित है जिसमें ब्लास्ट होने की कोई खतरा नहीं होता,मीटर के अनुसार बिल का भुगतान करना होगा। सुरक्षित और किफायती होगी आपूर्ति-पाइपलाइन गैस सेवा शुरू होने से आम जनता को समय पर सिलेंडर रिफिलिंग की समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही यह सुविधा आर्थिक रूप से किफायती और पर्यावरण व सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद अनुकूल साबित होगी। बैठक में एचसीजी के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिले में मुख्य नेटवर्क और घरेलू कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

रेलवे पार्सल गोदाम से 5 क्विंटल पनीर जब्त

रायपुर। रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल परिसर में बुधवार को करीब 500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया। पनीर की गुणवत्ता और उसकी शुद्धता को लेकर संदेह होने पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (फूड विभाग) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, जब्त किए गए पनीर को रेलवे पार्सल परिसर में रखा गया है। पनीर के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पनीर असली है या नकली तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं। बताया जा रहा कि अमरकंटक एक्सप्रेस से यह संदिग्ध पनीर आया है। पनीर का मालिक कौन है इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। फिलहाल खाद्य विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यदि जांच में पनीर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा।

प्रदेश में 1460 गौधामों की होगी स्थापना

रायपुर। गौधाम योजना का उद्देश्य प्रदेश में बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराना, उनके संरक्षण को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। गोधन हमारी ग्रामीण संस्कृति, कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार गोधन संरक्षण और बेसहारा मवेशियों की देखभाल के लिए गौधाम योजना को राज्यभर में चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है, जिससे गौसेवा की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ ही पशुधन संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।. संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं से प्राप्त जानकारी के अनुसार घुमन्तू एवं निराश्रित पशुधन के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर को 1460 गौधाम योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई। प्रथम चरण में ऐसे गौठानों का चयन किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है एवं जहां समस्त आवश्यक अधोसंरचना पूर्ण हैं। गौधाम योजना के प्राप्त 408 आवेदनों में से 151 को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई, जिसमें पंजीयन पूर्ण कर पशुओं के व्यवस्थापन की कार्यवाही की जा रही है। 42 गौधामों में लगभग 5109 पशुधन संरक्षित गौधाम योजना अंतर्गत ऐसी शासकीय भूमि जहां अधोसंचना पूर्ण हो एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप हो, जैसे गौठान को चिन्हांकित कर स्वयं सेवी संस्था, पंजीकृत गौशाला, एन.जी.ओ. एफ.पी.ओ. ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाना है। वर्तमान में 88 गौधामों का पंजीयन पूर्ण कर लिया गया है और 42 गौधामों में लगभग 5109 पशुधन संरक्षित है। कलेक्टर/जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा, पंचायत द्वारा प्रदायित अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जिला स्तर पर गठित समिति के भौतिक सत्यापन पश्चात, गौधाम के आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को प्रेषित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन आयोग के क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा हेतु प्रत्येक 03 माह में एक बार आयोजित बैठक में विस्तृत समीक्षा की जाती है, तत्पश्चात प्रशासकीय स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जाती है। आज हर मौसम में जीवन का आधार बना जल स्त्रोत प्रत्येक विकास खण्ड में उत्कृष्ट 10 गौठानों का किया जाएगा चयन प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात आयोग के साथ अनुबंध एवं पंजीयन पश्चात जिला प्रशासन के माध्यम से गौधाम में घुमन्तू पशुओं का व्यवस्थापन किया जाता है। पशुधन विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग नियम संशोधित कर गौधाम संचालन हेतु ग्राम पंचायत को प्राथमिकता दी गई। साथ-साथ शहरी गौठान को भी योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं शासन द्वारा स्वीकृत योजना में गौधाम निर्माण के लक्ष्य निर्धारित नहीं हैं, परन्तु अध्यक्ष गौ सेवा आयोग द्वारा परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक विकास खण्ड में उत्कृष्ट 10 गौठानों का चयन कर पूरे प्रदेश के 1460 गौधामों की स्थापना की जाएगीं। ग्राम पंचायत के माध्यम से गौधाम संचालन के नियम संशोधन एवं शहरी गौठानों को भी योजना में शामिल करने के पश्चात निश्चित रूप से भविष्य में गौधाम के संख्या में बढोतरी होगी। आवश्यकता अनुसार जिलों से गौधाम स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे है,

जिंदा महिला को कागजों में मृत बताकर जमीन हड़पने का आरोप: तहसीलदार, पटवारी समेत चार पर एफआईआर

*** फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नामांतरण और जमीन की दान-बिक्री का मामला: वर्षों बाद झिलमिली पुलिस ने दर्ज किया आपराधिक प्रकरण**

सूरजपुर/भैयाथान, 05 अगस्त 2026, द शूटर। जिले में राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों और कथित भू-माफियाओं की मिलीभगत के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं। कई मामलों में दशकों पुरानी जमीनें मूल भू-स्वामियों के नाम से हट जाती हैं और पीड़ितों को अपने ही अधिकार साबित करने के लिए वर्षों तक राजस्व न्यायालयों से लेकर अन्य अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला अब भैयाथान क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक जीवित महिला को कागजों में मृत दर्शाकर उनकी वैध कृषि भूमि का नामांतरण कराने और बाद में उसी जमीन का दान व विक्रय किए जाने के आरोप में झिलमिली पुलिस ने तत्कालीन तहसीलदार, हल्का पटवारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले में प्रारंभिक रूप से अपुष्ट सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार झिलमिली थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 185/2026 के अनुसार पुलिस ने वीरेन्द्रनाथ दुबे, तत्कालीन तहसीलदार संजय कुमार राठौर, तत्कालीन हल्का पटवारी एंजलिना भगत तथा कमलेश दुबे को आरोपी बनाया है। इनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं 61(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

पुलिस जांच और एफआईआर के अनुसार ग्राम कोयलारी निवासी शैलकुमारी दुबे ने वर्ष 1976 में संबंधित कृषि भूमि विधिवत खरीदी थी और वर्षों तक वह उनकी वैध संपत्ति रही। आरोप है कि वर्ष 2024 में कथित रूप से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और झूठे शपथ पत्र के आधार पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद राजस्व अभिलेखों से उनका नाम हटाकर भूमि का नामांतरण वीरेन्द्रनाथ दुबे के पक्ष में कर दिया गया।आरोप है कि नामांतरण आदेश के कुछ ही दिनों बाद भूमि का एक हिस्सा दानपत्र के माध्यम से कमलेश दुबे को तथा शेष हिस्से का विक्रय अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और विभागीय जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया फजीर्वाड़ा, धोखाधड़ी और षड्यंत्र के पर्याप्त आधार मिलने पर अपराध दर्ज किया गया।जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि जिस महिला को दस्तावेजों में मृत बताया गया, वह जीवित थीं और उनके जीवित होने के कई प्रमाण उपलब्ध हैं। वहीं, यदि कथित मृत्यु वर्ष 1967 में हुई थी तो वर्ष 1976 में उनके नाम से भूमि की खरीदी होना स्वयं कथित मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।मामले की जांच के दौरान बलरामपुर जिला पुलिस तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से भी अभिलेख प्राप्त किए गए। कथित मृत्यु प्रमाण पत्र के जारी होने की प्रक्रिया, रिकॉर्ड और हस्ताक्षरों में भी विसंगतियां सामने आने की बात एफआईआर में दर्ज है। कलेक्टर कार्यालय की विभागीय जांच में भी प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि शैलकुमारी दुबे जीवित हैं, जबकि उन्हें मृत मानकर नामांतरण आदेश पारित किया गया था।

फिलहाल झिलमिली पुलिस पूरे मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है। जांच के आधार पर अन्य व्यक्तियों की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी प्रकरण में शामिल किया जा सकता है। यह मामला केवल एक भूमि विवाद नहीं, बल्कि राजस्व अभिलेखों की विश्वसनीयता, प्रशासनिक जवाबदेही और आम नागरिक के संपत्ति अधिकारों से जुड़ा गंभीर प्रश्न बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित

रायपुर । छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना, कलाकारों का सम्मान बढ़ाना तथा कला दलों के सतत विकास को नई गति प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला (पारंपरिक व्यंजन) तथा छत्तीसगढ़ी सौंदर्यकला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, नया रायपुर स्थित कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ केवल ऐसे कलाकारों को मिलेगा जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 96 हजार रुपये से अधिक नहीं है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड तथा पैन कार्ड की छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। प्रविष्टियां भेजने का पता झ संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, सेक्टर-27, नया रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) 492018 आज हर मौसम में जीवन का आधार बना जल स्त्रोत प्रविष्टियां प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन भेजते समय लिफाफे पर मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना प्रदेश की समृद्ध लोक कला परंपराओं के संरक्षण, कलाकारों के सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

महाभारत में अश्वत्थामा बने प्रदीप रावत का अंतिम संस्कार:लगान-गजनी जैसी कई फिल्मों में दिखे थे; कल कैंसर से निधन हुआ था

प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुआ था। उनका मंगलवार को मुंबई में निधन हुआ।एक्टर प्रदीप रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई में परिवार के लोगों के अलावा रजा मुराद जैसे सेलेब्स भी पहुंचे।लगान और गजनी समेत कई फिल्मों में नजर आने वाले प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में मंगलवार शाम को निधन हो गया।

रजा मुराद अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदीप रावत के मैनेजर सिद्धार्थ तिवारी ने बताया था कि एक्टर कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें यह बीमारी दोबारा लौट आई थी। पिछले एक महीने से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था।

महाभारत में अश्वत्थामा का रोल निभाया था

प्रदीप रावत ने एक्टिंग करियर की शुरूआत बीआर. चोपड़ा के टीवी शो महाभारत से की थी। वे अश्वत्थामा के रोल में नजर आए थे। प्रदीप ने इसके बाद हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में काम किया।

हिंदी सिनेमा में वे लगान, सरफरोश, गजनी और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों में दिखाई दिए। तेलुगु फिल्म सई (रटी) से उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में कदम रखा और कई यादगार विलेन के किरदार निभाए। फिल्म गजनी में प्रदीप रावत का किरदार आमिर खान के किरदार की गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है।

फिल्म गजनी में प्रदीप रावत का किरदार आमिर खान के किरदार की गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है।

तमिल फिल्म गजनी (2005) में उनके डबल रोल को काफी पसंद किया गया। बाद में उन्होंने इसी भूमिका को हिंदी रीमेक गजनी में भी निभाया। इसके अलावा उन्होंने कन्नड़ फिल्म पैरोडी, मलयालम फिल्म चाइना टाउन, बंगाली फिल्म हीरो 420 और भोजपुरी फिल्म क्रैक फाइटर में भी एक्टिंग की थी।

आमिर खान को बहन ने डांट दिया था फिल्म लगान में देवा का किरदार पहले एक्टर मुकेश ऋषि को ऑफर हुआ था, लेकिन साउथ की कई फिल्मों में व्यस्त होने के कारण उन्होंने यह फिल्म नहीं की। इसके बाद यह रोल प्रदीप रावत को मिला था।

दरअसल, फिल्म सरफरोश में प्रदीप रावत का काम देखकर आमिर खान काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने आधी रात करीब 12 बजे प्रदीप के घर के लैंडलाइन पर फोन किया। उस समय प्रदीप घर पर नहीं थे। उनकी बहन ने फोन उठाया। ह्यमैं आमिर खान बोल रहा हूंह्व सुनकर उन्होंने इसे प्रैंक कॉल समझा। उन्होंने डांटते हुए कहा, ह्यक्यों बदमाशी कर रहे हो?

बिग बॉस में क्या सलमान के साथ नजर आएंगे शाहरुख

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का पहला प्रोमो मेकर्स ने जारी कर दिया है। इसमें सलमान खान बतौर होस्ट वापसी करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में सलमान ने 'करण-अर्जुन' का जिक्र कर एक नया सस्पेंस खड़ा कर दिया है। यह नया सीजन 6 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसका प्रसारण हर दिन रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर किया जाएगा।

इस बार फेस्टिव सीजन में बिग बॉस के सभी 6 भाषाओं वाले वर्जन एक साथ रिलीज किए जा रहे हैं। 'करण-अर्जुन' का जिक्र, शाहरुख के आने की अटकलें जारी किए गए प्रोमो में सलमान खान एक घोड़े के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के अंत में वे कहते हैं, ह्जो करण-अर्जुन में हुआ था, वह अब बिग बॉस में दोबारा होगा... तथास्टू! सलमान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रैंड प्रीमियर पर शाहरुख खान भी सलमान के साथ नजर आ सकते हैं।

सलमान खान ने सोहेल को दी आगे बढ़ने की सलाह:बोले- किसी को डेट करना शुरू करो; बेटे से कराई वीडियो कॉल में बात

एक्टर सलमान खान ने हाल ही में अपने छोटे भाई सोहेल खान को उनके तलाक के बाद आगे बढ़ने और किसी को डेट करने की सलाह दी। हाल ही में सलमान खान शो अलायंस के नए एपिसोड में पहुंचे थे, जिसमें सोहेल बतौर कंटेस्टेंट भाग ले रहे हैं। बातचीत के दौरान सलमान ने सोहेल और सीमा सजदेह की शादी का जिक्र करते हुए कहा कि हर रिश्ते में मुश्किल दौर और झगड़े आते हैं। उन्होंने कहा, ह्यतुम खुद पर कुछ दोष ले रहे हो। मैं समझता हूं कि तुम यह नहीं कहोगे कि यह आपसी फैसला था। मैंने सीमा के कुछ इंटरव्यू देखे, जिनमें उन्होंने कहा कि रिश्ता टॉक्सिक था और झगड़े होते थे।'

उन्होंने आगे कहा, 'हर कपल के बीच झगड़े होते हैं। यह आपके ऊपर है कि रिश्ते में बने रहना है या अलग होना है। एक भाई होने के नाते मैं जानता हूं कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसने भी की, लेकिन उस समय हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं थे।

सलमान बोले- अब किसी को डेट करो और आगे बढ़ो

सलमान ने सोहेल को नई शुरूआत करने की सलाह देते हुए कहा, ह्यकिसी को डेट करना शुरू करो। आगे बढ़ो। तुम जानते हो न कि हमारा दिमाग हमारे साथ कैसे खेल खेलता है? दिमाग की यही आदत है। चाहे जिंदगी की बाकी सारी चीजें कितनी भी अच्छी चल रही हों, लेकिन अगर एक भी ऐसी बात हो जो तुम्हें परेशान कर रही हो, तो तुम बाकी की 99.9% अच्छी चीजों को भूल जाते हो। उन्होंने आगे कहा कि फिर पूरा ध्यान उसी एक नेगेटिव बात पर टिक जाता है। तुम सोचते रहते हो, 'यार, ये चीज मेरे हित में नहीं हैह्व ये नेगेटिव हैह्व ये मुझे परेशान कर रही है और फिर तुम्हारा दिमाग बार-बार उसी एक बात पर जाता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। पिछले कुछ हफ्तों से परिवार को मिस कर रहे सोहेल की सलमान ने अपने फोन से बेटे निर्वाण से वीडियो कॉल पर बात कराई। बेटे से बात कर सोहेल इमोशनल और खुश हो गए।सोहेल और सीमा की पहली मुलाकात चंकी पांडे की सगाई की पार्टी में हुई थी।

मलाइका अरोड़ा ने की चप्पल पहनकर नई कार की पूजा:रिवीलिंग ड्रेस और हील्स पहनने पर भड़के लोग; 28 लाख की थार रॉक्स खरीदी

अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में नई महिंद्रा थार रॉक्स गाड़ी खरीदी है। कार की डिलीवरी के बाद वे अपने दोस्तों और स्टाफ के साथ गाड़ी की पूजा करती नजर आईं। पूजा के दौरान मलाइका के पैरों में सैंडल (हील्स) देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। बिना चप्पल-सैंडल उतारे और रिवीलिंग कपड़ों में नई गाड़ी की आरती उतारने पर लोगों ने मलाइका पर नाराजगी जताई और इसे सिर्फ फोटो खिंचवाने का दिखावा बताया है।

चप्पल पहनकर आरती उतारने पर भड़के यूजर्स सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मलाइका अरोड़ा स्ट्राइप्ड को-ऑर्ड सेट ड्रेस, डीप-नेक टॉप, गॉगल्स और हील्स पहने नजर आ रही हैं। उनके हाथ में पूजा की थाली है और वे गाड़ी पर तिलक लगाकर आरती उतार रही हैं। चप्पल पहनकर पूजा करने पर एक यूजर ने लिखा, ह्कम से कम अपने जूते तो उतार लेतीं, ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए पूजा करते हैं। दूसरे यूजर ने कमेंट किया, जूते पहनकर पूजा कौन करता है? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि पूजा श्रद्धा का काम है, कम से कम पारंपरिक और शालीन कपड़े पहनने चाहिए थे। 28 लाख की कार खरीदने पर फैन्स ने दी बधाई मलाइका ने अपनी इस नई महिंद्रा थार रॉक्स के लिए करीब 28 लाख रुपए खर्च किए हैं। गाड़ियों को फूलों की मालाओं से सजाया गया था। जहां एक तरफ कपड़ों और हील्स पहनकर पूजा करने की वजह से मलाइका ट्रोल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके फैन्स उनकी इस नई कामयाबी और शानदार कार खरीदने पर बधाई दे रहे हैं। मलाइका ने कहा था-अब सफाई नहीं देती अपनी लगातार होती ट्रोलिंग पर मलाइका अरोड़ा हमेशा बेबाकी से जवाब देती रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लोगों ने उनके करियर, कपड़ों और रिश्तों हर चीज को जज किया है।

मलाइका ने कहा था, जिस दिन से मैंने लोगों को सफाई देना बंद कर दिया, उस दिन से मैं आजाद महसूस करने लगी। मुझे बोल्ड और बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

ब्रेट ली ने प्रीति संग अफेयर की अफवाहें खारिज कीं:बोले- हम अच्छे दोस्त थे और हैं, कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने हाल ही में मुंबई दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के साथ अपने अफेयर की अफवाहों को पूरी तरह खारिज किया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में जब ब्रेट ली से उनका नाम बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ जुड़ने की अफवाहों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'ये रही आपकी खबर... मैंने कभी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को डेट नहीं किया।'

उन्होंने आगे कहा, ह्यप्रीति जिंटा और मैं पहले भी बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी हैं। उस समय वह पंजाब टीम की मालकिन थीं। वह बेहद समझदार महिला हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। ऐसी खबरों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा सच पता था। लोग जितनी चाहें अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें अपने ऊपर असर नहीं करने दिया। ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए साल 2008 से 2010 तक खेला था।

ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के लिए साल 2008 से 2010 तक खेला था। प्रीति जिंटा और ब्रेट ली की पर्सनल लाइफ

प्रीति जिंटा ने साल 2016 में अमेरिकी फाइनेंशियल एनालिस्ट जीन गुडइनफ से शादी की थी। दोनों की शादी लॉस एंजिल्स में निजी समारोह में हुई। साल 2021 में यह कपल सरोगेसी के जरिए जुड़वां बच्चों, बेटे जय और बेटी जिया, का माता-पिता बना। फिलहाल परिवार लॉस एंजिल्स में रहता है।

वहीं, ब्रेट ली ने 2006 में एलिजाबेथ केम्प से पहली शादी की थी। दोनों का एक बेटा है, लेकिन 2009 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद 2014 में ब्रेट ली ने लाना एंडरसन से दूसरी शादी की। इस शादी से उनके दो बच्चे हैं और वह ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।

मुंबई से पुराना नाता

ब्रेट ली ने इंटरव्यू में बताया कि उनका भारत से कनेक्शन 1994 में शुरू हुआ था, जब वे पहली बार ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के साथ मुंबई आए थे। ली ने कहा कि मुंबई उनके दिल के बहुत करीब है और यह शहर उन्हें अपने दूसरे घर जैसा लगता है। उन्होंने मुंबई की बारिश और यहां की एनर्जी की तारीफ की। ली के अनुसार, मुंबई की बारिश शहर के मिजाज का एक अहम हिस्सा है, जो इसे और खास बनाती है।

ऑटो रिक्शा और 'मुकाबला' गाना

मुंबई में शूटिंग के दौरान ऑटो रिक्शा में बैठकर ली को अपने शुरूआती ट्रेनिंग के दिन याद आ गए। उन्होंने बताया कि 1994 में वे अपनी क्रिकेट किट लेकर ऑटो में ही ट्रेनिंग के लिए जाते थे। ली ने बताया कि भारत में सुना गया उनका पहला गाना 'मुकाबला' था, जो उन्होंने ऑटो रिक्शा में सुना था। तब उन्हें हिंदी समझ नहीं आती थी, लेकिन संगीत पसंद आया था। बाद में उन्होंने इस गाने का मतलब समझा और अब जब भी भारत आते हैं, तो यह गाना जरूर सुनते हैं। एआर रहमान का इंटरव्यू लेना उनके लिए एक शानदार अनुभव था।

सन्नी देओल बोले- 'भारत मेरी मां तो पाकिस्तान मौसी है':फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान दिया बयान, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग

फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज से पहले सनी देओल अपने एक बयान को लेकर विवादों में आ गए। पटना में फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को मौसी बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया।

दरअसल सनी से सवाल किया गया कि यह मूवी, जो पाकिस्तान में शूट की गई है, तो आप पाकिस्तान को एक देश या माहौल के तौर पर कैसे देखते हैं? क्या आप कुछ बताना चाहेंगे?

इस पर सनी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान में नहीं हुई, बल्कि फिल्म हिंदुस्तान में ही शूट हुई है।उन्होंने आगे कहा, हम कोई ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि पूरा देश एक ही था। जैसे पापा ने कहा था कि मेरी मां (भारत) तो वो मेरी मौसी (पाकिस्तान) है, जो आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। हम सब एक तरह से हैं, तो कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं।

सनी देओल के इस बयान पर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी। कुछ यूजर्स ने उनके बयान की आलोचना की। एक यूजर ने लिखा, सनी देओल हर नए वीडियो से अपनी छवि को और नुकसान पहुंचा रहे हैं।

दूसरे ने कहा, मुझे यह व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है।

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, पूरे परिवार को बर्बाद करने वाली मौसी वाली बात सही है।

फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल दमदार एक्शन करते नजर आ रहे हैं।

'बंटवारा 1947' विभाजन की कहानी पर आधारित है

बता दें कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की कहानी हिंसा, विस्थापन और पारिवारिक संघर्ष से जूझ रहे एक परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में सनी देओल के साथ शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म की रिलीज से पहले सनी देओल रविवार देर शाम पटना में स्थित तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मस्थान पर मत्था टेककर आशीर्वाद लिया।

गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों ने सनी देओल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया और गुरु घर की परंपराओं से अवगत कराया गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा लिया।

किशोर दा ने टेबल मंगवाया, उस पर लेट गए और गाने लगे! मजाक-मजाक में रिकॉर्ड हुआ 80 के दशक का ब्लॉकबस्टर गाना

किशोर दा और उनके गीतों के मुरीद तो हम सभी हैं, लेकिन आज उनकी जयंती पर एक मजेदार किस्सा उनके एक ब्लॉकबस्टर गाने के बनने की। 80 का वो दशक और जब मजाक-मजाक में रिकॉर्डिंग रूम में टेबल पर लेटकर गाया ऐसा गाना, आज भी गुनगुनाए बिना नहीं रह पाती है दुनिया।

किशोर कुमार कितने हरफनमौला थे, यह बताने की जरूरत नहीं है। चाहे फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग हो, भजन गाना हो, गजल या फिर कव्वाली, उनका अंदाज सबसे जुदा होता है। भारतीय संगीत के इतिहास के सबसे पॉपुलर, सबसे महान और सबसे प्रभावशाली गायकों में एक किशोर दा की 04 अगस्त 2026 को जयंती है। साल 1929 में खंडवा (अब मध्य प्रदेश) में पैदा हुए आभास कुमार गांगुली उर्फ किशोर कुमार अपने गीतों को 'योडलिंग' और अलग-अलग आवाजों में गाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनके गाने तो सुपरहिट हैं ही, उन गानों की रिकॉर्डिंग और बनने के किस्से भी कम दिलस्प नहीं है। आज हम किशोर दा के एक ऐसे ही मस्त मिजाज रिकॉर्डिंग की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। उस दिन रिकॉर्डिंग रूप में भी बप्पी दा से लेकर आशा भोसले तक, सब हैरान थे कि किशोर दा ये क्या कर रहे हैं।

हिंदी सिनेमा के सबसे सेलिब्रेटेड सिंगर किशोर दा ने 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता था। जबकि 28 बार नॉमिनेशन पाया था। यह बॉलीवुड के इतिहास में इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने और नॉमिनेट होने का रिकॉर्ड है। उन्हें 1985 में मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि उनकी याद में 1997 में, मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए 'किशोर कुमार पुरस्कार' शुरू किया।

'शराबी' फिल्म का गाना 'इन्तहा हो गई इंतजार की'

किशोर दा सिंगिंग, म्यूजिक और एक्टिंग को सिर्फ अपना काम नहीं मानते थे। बल्कि इन तीनों विधाओं से उन्हें अथाह प्रेम था। ऐसा प्यार, जो उन्हें इन विधाओं में प्रयोग करते रहने, इसका आनंद लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता था।

रिहायशी बस्ती तक पहुंचा हाथी, तीन घर किए तबाह, फसलें रौंदी... करीब छह दिनों से दहशत में जी रहे ग्रामीण

सूरजपुर, 5 अगस्त 2026 द शूटर। जंगल और इंसानों के बीच बढ़ती दूरी का दर्द अब गांवों की चौखट तक पहुंच चुका है। रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के बकीरामा क्षेत्र में बीते करीब छह दिनों से विचरण कर रहा एक जंगली हाथी अब रिहायशी इलाके में घुस आया। देर रात हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाते हुए तीन मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और खेतों में खड़ी फसलों को भी बुरी तरह रौंद डाला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय और अनिश्चितता का माहौल है।ग्रामीणों का कहना है कि दिन ढलते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता है। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, महिलाएं और बुजुर्ग पूरी रात जागकर गुजारने को मजबूर हैं। हर आहट पर लोगों की नजर दरवाजे की ओर चली जाती है कि कहीं हाथी फिर से गांव की ओर न आ जाए। जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके सामने सिर छिपाने और रोजमर्रा की जिंदगी संभालने की नई चुनौती खड़ी हो गई है।ग्रामीणों ने बताया कि हाथी ने खेतों में लगी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में बर्बाद हो गई। ऐसे में आर्थिक नुकसान के साथ-साथ भविष्य की चिंता भी लोगों को सता रही है।घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। विभाग का अमला हाथी को सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथी के करीब जाने की कोशिश न करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी गतिविधि की तत्काल सूचना वन विभाग को दें।

हालांकि, लगातार करीब छह दिनों से हाथी के गांवों के आसपास डटे रहने से लोगों की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हाथी को पूरी तरह जंगल की ओर नहीं भेजा जाता, तब तक वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि किसी बड़ी जनहानि की आशंका को समय रहते टाला जा सके।

संत रविदास जी की पावन मिट्टी के कलश का स्वागत, श्रद्धा और समरसता से सराबोर हुई सूरजपुर की फिजा

सूरजपुर, 5 अगस्त 2026 द शूटर। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा का अनुपम दृश्य सूरजपुर शहर में देखने को मिला, जब रायपुर से लाई गई उनकी पावन मिट्टी के कलश का पूरे सम्मान और भक्तिभाव के साथ भव्य स्वागत किया गया। कलश के नगर आगमन के साथ ही वातावरण जय गुरु रविदास के जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं की आस्था मानो सड़कों पर उमड़ पड़ी।सुबह करीब 11 बजे महामाया चौक पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधिवत पूजन कर पावन कलश का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली सोनी, जिला महामंत्री शशिकांत, जिला कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष देव गुप्ता, मंडल अध्यक्ष अरविंद, विजय राजवाड़े, महिला मोर्चा की पदाधिकारी, पार्षद, एल्डरमैन सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे।स्वागत के बाद महामाया चौक से मानपुर चौक होते हुए गायत्री मंदिर तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। रैली के दौरान श्रद्धालु संत रविदास जी के भजनों और जयघोष के साथ आगे बढ़ते रहे। नगर के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने श्रद्धापूर्वक कलश के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। पूरा शहर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के रंग में रंगा नजर आया।गायत्री मंदिर पहुंचने पर संत रविदास जी की पावन मिट्टी के कलश की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान संत रविदास जी के जीवन दर्शन, मानव समानता, सामाजिक समरसता और भाईचारे के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलने तथा उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि मनुष्य की पहचान उसके कर्म, विचार और मानवता से होती है, न कि किसी भेदभाव से। उनके आदर्श आज भी समाज को प्रेम, समानता और सद्भाव के सूत्र में बांधने की प्रेरणा देते हैं। कुलमिलाकर श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता का संदेश देती इस शोभायात्रा में शहरवासियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। आस्था से सजी यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संत रविदास जी के मानवीय मूल्यों और सामाजिक एकता के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का भावपूर्ण प्रयास बन गई।

लाइफ लाइन एक्सप्रेस: अब इलाज घर के करीब, रामानुजनगर से शुरू हुआ पंजीयन अभियान

*** गांव-गांव तक पहुंचेगी जानकारी, जरूरतमंद मरीजों से समय रहते पंजीयन कराने की अपील**

रामानुजनगर, 05 अगस्त 2026 द शूटर। कई बार आर्थिक तंगी और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोग इलाज नहीं करा पाते। ऐसे ही जरूरतमंद मरीजों के लिए इस बार लाइफ लाइन एक्सप्रेस एक नई उम्मीद लेकर आ रही है। जिले में प्रस्तावित इस विशेष स्वास्थ्य परियोजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को रामानुजनगर के सामुदायिक भवन में जागरूकता एवं पंजीयन अभियान की शुरूआत की गई।कार्यक्रम में जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सचिवों, पंचायत कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को अभियान की जानकारी देते हुए निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने गांवों में ऐसे लोगों की पहचान करें, जिन्हें इस निशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सकता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मरीज जानकारी के अभाव में इस अवसर से वंचित न रह जाए।जनपद पंचायत रामानुजनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की 256वीं लाइफ लाइन एक्सप्रेस परियोजना के लिए आवेदन प्रपत्र सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचा दिए गए हैं। उन्होंने सचिवों से कहा कि ग्राम सभाओं, मुनादी, दीवार लेखन और अन्य स्थानीय माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र मरीजों का शीघ्र पंजीयन कराया जाए। उनका कहना था कि समय पर पंजीयन ही इस योजना का लाभ दिलाने की पहली शर्त है।उन्होंने जानकारी दी कि 16 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर लाइफ लाइन एक्सप्रेस के माध्यम से पूरी तरह निशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान आंखों की जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन, कान संबंधी जांच एवं सर्जरी, जन्मजात मुड़े हुए हाथ-पैर का उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, दांतों का उपचार तथा महिलाओं के लिए स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन कराने वाले मरीजों को अपने साथ आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। भर्ती होने वाले प्रत्येक मरीज के साथ केवल एक सहयोगी को रहने की अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम के अंत में जनपद पंचायत सीईओ ने सभी ग्राम पंचायतों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों तक इस जानकारी को प्राथमिकता से पहुंचाएं और उनका समय पर पंजीयन सुनिश्चित करें। वहीं उपस्थित पंचायत सचिवों और कर्मचारियों ने भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने तथा अधिक से अधिक पात्र मरीजों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान से जोड़ने का भरोसा दिलाया।

पुरानी रंजिश और जमीन विवाद ने फिर बहाया खून, दो मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर, 05 अगस्त 2026, द शूटर। छोटी-छोटी रंजिशें जब कानून और समझदारी की सीमा लांघ जाती हैं तो उसका अंजाम हिंसा और परिवारों की पीड़ा के रूप में सामने आता है। जिले में ऐसे ही दो अलग-अलग मामलों में पुरानी रंजिश और जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दोनों घटनाओं में गंभीर रूप से घायल लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।पहला मामला थाना प्रेमनगर क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई की रात ग्राम गौरीपुर निवासी मटुकधारी यादव की दुकान पर ग्राम कंचनपुर निवासी रविन्द्र रजक पेट्रोल पंप की उधारी का पैसा लेने पहुंचा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर लक्ष्मण यादव, संदीप यादव, जमुना प्रसाद यादव और कमलेश यादव लाठी-डंडों से लैस होकर वहां पहुंचे और विवाद करते हुए रविन्द्र रजक पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रविन्द्र को पहले प्रेमनगर अस्पताल और बाद में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया।मामले में थाना प्रेमनगर में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस अधीक्षक आईपीएस योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने दबिश देकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने घटना को स्वीकार किया, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त लाठियां बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया।वहीं दूसरा मामला चौकी बसदेई क्षेत्र के ग्राम जूर का है, जहां लंबे समय से चले आ रहे जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़िता हसीना बीबी ने पुलिस को बताया कि खेत में मौजूद रहने के दौरान अयुब अंसारी, उसके परिजन और भतीजे ने गाली-गलौज करते हुए विवाद शुरू कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे उनके पति मोहम्मद यासीन के साथ आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं बख्शा गया।प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी रही। मुखबिर की सूचना पर चौकी बसदेई पुलिस ने ग्राम सरमा में छिपे आरोपी असलम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जमीन विवाद को लेकर मारपीट करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था। मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।दोनों मामलों में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि व्यक्तिगत विवाद यदि समय रहते संवाद और कानूनी प्रक्रिया से नहीं सुलझाए जाएं, तो उनका परिणाम पूरे परिवारों के लिए दर्द और संकट का कारण बन जाता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर किया जाए।

शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी, टीचर्स एसोसिएशन ने बीईओ से की सार्थक पहल

सूरजपुर, 05 अगस्त 2026, द शूटर। शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि शिक्षकों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों का समय पर निराकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसी उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, सूरजपुर ने शिक्षक संवर्ग की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष भूपेश सिंह के नेतृत्व में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर हरेंद्र सिंह तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर अवधेश कुमार साहू से अलग-अलग भेंट कर सेवा पुस्तिका, सीजीपीएफ पासबुक, वरिष्ठता सूची में त्रुटियों और अवकाश संबंधी मामलों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में चंद्रविजय सिंह, पीतांबर सिंह मरावी, बिजेंद्र साहू, गौरीशंकर पांडेय, रामकुशल तिवारी, राजेंद्र साहू एवं अनुज राजवाड़े शामिल रहे।चर्चा के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं का संधारण लगातार किया जा रहा है और सभी शिक्षक कार्यालय में आकर उसका अवलोकन कर आवश्यक प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सीजीपीएफ पासबुक का संधारण भी जारी है। जिन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका या सीजीपीएफ पासबुक अब तक पूर्ण नहीं हो सकी है, वे विद्यालयीन समय के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। साथ ही संभाग स्तर से सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने जिला स्तर से जारी सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में सामने आई त्रुटियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। इस पर बीईओ ने आश्वस्त किया कि विकासखंड से संबंधित शिक्षकों की प्रविष्टियों का सेवा पुस्तिका से मिलान कर आवश्यक सुधार के लिए उच्च कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। रामानुजनगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी अवधेश कुमार साहू के साथ हुई चर्चा में भी सेवा पुस्तिका, सीजीपीएफ पासबुक, वरिष्ठता सूची में संशोधन तथा शिक्षकों के अवकाश आवेदनों के समयबद्ध निराकरण पर जोर दिया गया। उन्होंने सभी मामलों का निर्धारित समय सीमा में समाधान करने का भरोसा दिलाया।बैठक में यह भी सामने आया कि कलेक्टर सूरजपुर द्वारा परामर्शदात्री समिति की बैठक में दिए गए निदेशों के अनुरूप सभी विकासखंडों में शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यों के निष्पादन में कठिनाइयां आ रही हैं। शिक्षकों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त लिपिकीय एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भूपेश सिंह ने कहा कि जिला एवं विकासखंड कार्यालयों में कार्यरत गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को मूल विद्यालयों में भेजे जाने के बाद कार्यालयों पर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में पदस्थ गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार संबद्ध कर कार्यालयीन कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किया जाए, ताकि शिक्षकों के लंबित प्रकरणों का समय पर निराकरण हो सके।

एसोसिएशन ने उम्मीद जताई कि प्रशासन और शिक्षक संगठन के बीच सकारात्मक संवाद का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और शिक्षकों की वर्षों से लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित होगा।

नई जिम्मेदारी के साथ बढ़ीं उम्मीदें, कर्मचारी संघ ने किया संयुक्त संचालक डॉ. राजेश कुमार सिंह का आत्मीय स्वागत

अम्बिकापुर, 05 अगस्त 2026, द शूटर। किसी भी विभाग में नए नेतृत्व का आगमन केवल पदभार ग्रहण करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे कर्मचारियों की नई उम्मीदें और अपेक्षाएं भी जुड़ जाती हैं। शिक्षा विभाग सरगुजा में संयुक्त संचालक के रूप में डॉ. राजेश कुमार सिंह की नियुक्ति पर भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जब छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला सरगुजा के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे सौजन्य मुलाकात कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।प्रदेश महामंत्री आनंद यादव के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. सिंह को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। मुलाकात केवल औपचारिक स्वागत तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों की वर्षों से लंबित विभिन्न समस्याओं पर भी गंभीरता से चर्चा की गई।संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की कई सेवा संबंधी समस्याएं लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने नवपदस्थ संयुक्त संचालक से अपेक्षा जताई कि कर्मचारियों की जायज मांगों और विभागीय समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

डॉ. राजेश कुमार सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की समस्याओं का नियमानुसार एवं संवेदनशीलता के साथ समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग में बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और सकारात्मक कार्य वातावरण स्थापित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।बैठक के बाद कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि डॉ. सिंह के नेतृत्व में शिक्षा विभाग सरगुजा में प्रशासनिक कार्यों में नई गति आएगी और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण की दिशा में सार्थक पहल देखने को मिलेगी।इस अवसर पर सहायक संयुक्त संचालक अनील अग्रवाल भी मौजूद रहे।कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री आनंद यादव, संभागीय अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन रंजीत सारथी, संभागीय अध्यक्ष राजेश सोनी, संभागीय उपाध्यक्ष सुधीर राणा, संभागीय सचिव चन्द्रदेव चक्रधारी, संभागीय कोषाध्यक्ष रामजन्म यादव, जिला अध्यक्ष सरगुजा संजय यादव, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष माधुरी जायसवाल, उपाध्यक्ष आशा पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष बृजेश मिश्रा सहित कर्मचारी संघ के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- रूपेश दुबे द्वारा आर्यन ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, पॉवर हाउस रोड नमना कला अम्बिकापुर, सरगुजा, छ0ग0 से मुद्रित एवं मेन रोड प्रतापपुर, खोरमा, जिला- सूरजपुर, छ0ग0 से प्रकाशित। संपादक- प्रवीण दुबे* (* समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। फोन- 07777271215